सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 198, नई दिल्ली । शुक्रवार, 27 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 10000 बस मार्शल अब बर्बादी की कगार तक पहुंचे गए हैं...
06 आवास की तलाश में हिंसक होते जीव
08 सरिता आगलेचा ने सीआई एमए ऑपरेशनल केस स्टडी किया पुरा

सरकारी खर्चे में कटौती और राजस्व में इजाफे के तहत आज फिर आया परिवहन विभाग के आला अधिकारी का नया आदेश

संजय बाटला

नई दिल्ली। हम आपको अपने जानकर सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 दिन पहले ही सूचना दे चुके हैं की परिवहन विभाग के आला अधिकारी रोहिणी, वजीरपुर और मॉल रोड शाखा के विलय के जल्द आदेश जारी करने वाले हैं और इन सभी शाखाओं को विलय कर मॉल रोड शाखा में कार्यों के लिए जाने के दिशा निर्देश जारी करने वाले है। आज आदेश जारी हो गए और रोहिणी और वजीर पुर शाखा में ताले लगाने का समय घोषित कर दिया गया। अचम्बा इस बात का है की न्यायिक प्रक्रिया को अपनाए बिना परिवहन विभाग सिर्फ राजस्व में इजाफे को देखते हुए आदेश करता जा रहा है। इस प्रकार के आदेशो को देखते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्य सचिव और उपराज्यपाल चुप हैं इसका अर्थ साफ है की उन सभी की सहमति परिवहन विभाग के आला अधिकारी को प्राप्त है। हमने कुछ दिन पहले यह बताया था की दिल्ली में सभी परिवहन विभाग की क्षेत्रीय शाखाएं नियमानुसार उपराज्यपाल की सहमति प्राप्त कर जनहित में जनता को उनके घर के निकट सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर खोली गई थी ना की किसी आला अधिकारी के आदेश से। गैजेट नोटिफिकेशन से जनहित में खोली गई क्षेत्रीय शाखाओं को कोई भी अपनी इच्छा से सिर्फ सरकार के खर्चे की कटौती और राजस्व में इजाफे के उदेश्य से बंद करने की घोषणा या आदेश कैसे जारी कर सकता है। **पर यह दिल्ली है और आदेश जारी करने वाला परिवहन विभाग का आला अधिकारी** जिसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिशा निर्देश की कोई मान्यता नहीं तो उपराज्यपाल की मान्यता की बात तो सोचना ही दूर है वह भी जब वह आदेश ही सरकारी खर्चे में कटौती और राजस्व में इजाफे के उद्देश्य से जारी हो। **जनहित से ज्यादा आवश्यक है परिवहन विभाग के आला अधिकारी के लिए राजस्व इजाफा और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है दिल्ली को सुरक्षित विश्वसनीय सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध करवाने वाले सरकारी निकाय डीटीसी को पिछले 10 सालो में जनता को सेवा उपलब्ध करवाने के लिए एक भी बस ना खरीद कर देना।**

अब दिल्ली में परिवहन विभाग के मात्र 5 क्षेत्रीय कार्यालयो से ही कार्य किया जा रहा है जव की आज की तारीख में भी गैजेट नोटिफिकेशन के तहत दिल्ली में 13 क्षेत्रीय शाखाएं कार्यरत है। **यह है दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली के प्रशासक उपराज्यपाल का मिला जुला तोहफा।**

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT (ADMIN BRANCH)
5/9, UNDER HILL ROAD: DELHI-110054

F. No. DC/Ops/Tpt/2024/23/ 53515 Dated 26/09/2024

ORDER

In the interest of enhancing operational efficiency, optimizing resources utilization and improving public service delivery and also due to the abysmal conditions of Rohini and Wazirpur office, it has been decided to merge the zonal office of Delhi Transport department located at Mall Road, Rohini zonal office and Wazirpur Zonal Office into a single combined unit at the Mall Road (North Zone) office of Transport department GNCTD.

All the administrative, operational and public facing functions currently carried out at Wazirpur zonal office shall be transferred to the Mall Road(North zone) zonal office with effect from 30th September 2024 and Rohini zonal office shall be transferred to the Mall Road(North zone) zonal office with effect from 07th October 2024.

Driving test tracks at three locations to work under concerned MVI/Inspector/Foreman who shall report to DTO(Mall Road). DTO offices of Rohini and Wazirpur to be locked under watch of a guard and a clear board will be displayed at DTO Office Rohini and Wazirpur depicting that for office work, the applicant may contact DTO(Mall Road) at the following address
"Mall Road Authority, Transport Department, GNCTD, Timarpur, Delhi-110054"

This issues with the approval of competent authority.

26/9/24
Deputy Commissioner (Admin)

F. No. DC/Ops/Tpt/2024/23/ 53515 Dated: 26/09/24

Copy to:
1. PA to Principal Secretary cum Commissioner Transport GNCTD
2. PA to Special Commissioner (Operation) Transport GNCTD
3. PA to Deputy Commissioner (Operation) Transport GNCTD
4. All District transport Officer Transport GNCTD
5. Senior System Analyst to upload it on department website.

26/9/24
Deputy Commissioner (Admin)

आदेश की हिंदी प्रति

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार परिवहन विभाग (प्रशासन शाखा) 5/8, अंडर हिल रोड दिल्ली-110054 एफ. सं. डीसी/ओपे/टीपी2024/23 53515

परिचालन दक्षता बढ़ाने, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम बनाने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाने के हित में तथा रोहिणी और वजीरपुर कार्यालय की दयनीय स्थिति के कारण, यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के परिवहन विभाग के मॉल रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, रोहिणी क्षेत्रीय कार्यालय और वजीरपुर क्षेत्रीय कार्यालय को मिलाकर परिवहन विभाग जीएनसीटीडी के मॉल रोड (उत्तरी क्षेत्र) कार्यालय में एक संयुक्त इकाई बना दी जाए।

वर्तमान में वजीरपुर जोनल कार्यालय में किए गए सभी प्रशासनिक, परिचालन और सार्वजनिक कार्यों को 30 सितंबर 2024 से मॉल रोड (उत्तरी क्षेत्र) जोनल कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और रोहिणी जोनल कार्यालय को 07 अक्टूबर 2024 से मॉल रोड (उत्तरी क्षेत्र) जोनल कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

तीन स्थानों पर ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होंगे, जहां संबंधित एमवीआई/इंस्पेक्टर/फोरमैन काम करेंगे, जो डीटीओ (मॉल रोड) को रिपोर्ट करेंगे। रोहिणी और वजीरपुर के डीटीओ कार्यालयों को एक गार्ड की निगरानी में बंद रखा जाएगा और डीटीओ कार्यालय रोहिणी और वजीरपुर में एक स्पष्ट बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें दर्शाया जाएगा कि कार्यालय के काम के लिए, आवेदक संपर्क कर सकता है।

डीटीओ (मॉल रोड) निम्नलिखित पते पर
"मॉल रोड अथॉरिटी, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी, तिमारपुर, दिल्ली-110054"

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाएगा।
22619/24 उपायुक्त (प्रशासन) दिनांक 26/09/24
उप आयुक्त (प्रशासन)
एफ. सं. डीसी/ऑप्स/टीपीटी/2024/23/
कॉपी:
1. प्रमुख सचिव सह आयुक्त परिवहन जीएनसीटीडी के पीए
2. विशेष आयुक्त (संचालन) परिवहन जीएनसीटीडी के पीए
3. डिप्टी कमिश्नर (ऑपरेशन) परिवहन जीएनसीटीडी के पीए
4. सभी जिला परिवहन अधिकारी परिवहन जीएनसीटीडी
5. वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

क्या दिल्ली की जनता जानती है 4 नवम्बर 2020 के बाद परिवहन विभाग द्वारा जो लर्निंग लाइसेंस, लाइसेंस, बेज, आरसी या वाहन परमिट जारी किया हैं उनमें से अधिकांश एमवी एक्ट के अनुसार मान्य नहीं है

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग के एडमिन शाखा के आला अधिकारी द्वारा इन कार्यों को करने के लिए जिन अधिकारियों को पदों पर आसीन किया वह ना तो एमवी एक्ट के अनुसार ना ही उच्चतम न्यायालय के अनुसार, ना ही कैट के अनुसार और ना ही दिल्ली उपराज्यपाल के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लर्निंग लाइसेंस, लाईसेंस, बेज आरसी या वाहन परमिट जारी करने का अधिकार रखते हैं। अब सवाल यह उठता है की आखिर जिस अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा यह दस्तावेज जारी किए गए वह जारी करने की योग्यता ही नहीं रखते तो उन के द्वारा जारी दस्तावेज किस आधार पर मान्य हो सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग के एडमिन शाखा के आला अधिकारी के द्वारा इन पदो पर किस प्रकार ऐसे अधिकारियो को जिनके पास इन दस्तावेजों को जारी करने की शक्ति ही प्राप्त नहीं को पदों पर आसीन करने की इजाजत कैसे परिवहन आयुक्त से प्राप्त कर उन्हें आसीन किया। सवाल यह भी उठता है की जनता को ऐसे आवश्यक दस्तावेज प्रमाण जिसका न्याय की दृष्टि में कोई

ओचित्य नहीं एक सरकारी विभाग कैसे जारी करवाता रहा? सबसे मुख्य सवाल यह है किसी अन्य द्वारा अगर निम्न दस्तावेज को जारी करने वाले अधिकारी की मान्यता को न्यायलय में चुनौती दे दी तो क्या परिवहन विभाग सभी दस्तावेज जो जनता की दृष्टी में मान्य है को अमान्य सिद्ध हो जाने से बचाने का विश्वाश दे सकता है। दिल्ली के सभी नागरिकों से हमारी अपील है की वह स्वयं अपने दस्तावेज की जांच करें की परिवहन विभाग के एडमिन शाखा के आला अधिकारी की कृपा से आपका दस्तावेज जारी करने वाला अधिकारी न्यायिक दृष्टि से जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी था या नहीं। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश की कापी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है।

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT
5/9 UNDER HILL ROAD: DELHI-110054

No. /Admin/Tpt/2020/[illegible]/2423 Dated: 04/11/2020

ORDER

The following officials are hereby deployed as inspectors of Transport Department as defined in Rule 2(g) of DMVR in the zones mentioned herein below:

SN	Name of official	Designation	Place of Deployment
1	Sh. Virender Pal Sharma	Foreman	ARU Burari
2	Sh. Sajjan Kumar	-do-	VIU, Jhuljhuli
3	Sh. Aditya Prakash Gupta	Foreman	Surajmal Vihar
4	Sh. Yashpaul Singh	Foreman	VIU Burari
5	Sh. Amit Kr. Chaudhary	Asstt. Foreman	Wazirpur
6	Sh. Surjit Gahlot	Asstt. Foreman	New Delhi
7	Sh. Ajit Kumar	Asstt. Foreman	Rohini
8	Sh. Mukesh Sharma	Foreman	Mall Road
9	Sh. Sunil Chandana	ASO	Vasant Vihar
10	Ms. Rashmi Jain	ASO	Surajmal Vihar

The above officials shall assist the MLOs in discharging the duties of non-technical nature i.e. issue of learning licence, change of address in DL, RC, duplicate licence, renewal of licence, transfer of vehicle, issuance of conductor & driver badge and removal of hypothecations etc. The MLO shall remain the licencing and registration authority under the rule.

They will not take up any work which is exclusively within the domain of the MVI having technical qualification i.e. taking skill test and inspection of motor vehicles etc.

The MLOs are hereby directed to assign them specific non-technical works relating to DL and RC to provide prompt services to the general public.

This issues with the approval of competent authority.

(Ajit Kumar)
Admn. Officer

To
1. Officials concerned
2. Dy. Commissioner (Ops-I, II & III)
3. MLOs

Copy for information to –
1. OSD to Secretary-cum-Commissioner (Transport)
2. Spl. Commissioner (Ops)

पेनिक बटन के नाम पर अरबो रुपये के घोटाले का पर्दाफास करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित

79/c

GOVT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
COMPUTER BRANCH: TRANSPORT DEPARTMENT
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI -110054

F.DTO/VIU/2022/322/075779197/ Dated: 19/09/2024

ORDER

It is to inform that a Memorandum of Understanding (MoU) has been signed on 27/08/2024 by NIC, NICSI, and Transport Department, Govt. of NCT of Delhi for the implementation of Backend System and Monitoring Centre for Vehicle tracking and monitoring for public service vehicles as per AIS-140 standard from funds received from MORTH under Nirbhaya Framework.

In this regard, all the owner of Public Service vehicle (PSV) are required to do the transition from old DIMTS managed backend system to the new Vehicle Location Tracking (VLT) and Emergency Alert System (EAS) backend system. Further, for smooth transition it is also requested as under:

1. Vehicle owners and Bus operators to cooperate with VLTD vendors to verify the functionality of the backend system for monitoring and tracking of vehicle managed by NIC.
2. An OTP will be sent on mobile of the Vehicle owners for the verification and activation process to complete the onboarding of vehicles to the VLT and EAS backend. Without the same, the onboarding of the vehicle cannot be finalized.
3. DTO(VIU Burari) and DTO(VIU Jhuljhuli) as well as Assistant Secretary (STA) and all DTOs to check the functionality of backend tracking at the time of fitness of vehicle, Permit related works and during registration of new vehicle, for all vehicles which qualifies under rule 125H of CMVR for maintaining VLTD based Vehicle tracking and emergency alert system.
4. Deputy Commissioner (Bus Transport) to coordinate with all GCC operator as well as cluster buses to get onboarded on the backend system managed for monitoring of vehicle by NIC
5. This whole process of backend system for monitoring of vehicle is without any charge from the vehicle owner and vehicle owner to cooperate to get their vehicle onboarded on the backend system for monitoring of vehicle.

This issues with the approval of competent authority.

Special Commissioner (VIU/IT)

Copy to:
1. PS to Pr. Secretary-cum-Commissioner, Transport department GNCTD
2. Special Commissioner (Bus Transport) Transport Department GNCTD.
3. All DTOs including DTO (VIU Burari) and DTO (VIU Jhuljhuli)
4. Deputy secretary STA.
5. Deputy Commissioner (Taxi Unit)

Tax Invoice

RAFFLE AUTOMOTIVE
(NIPPON AUTHORISED DELER)
SHOP NO-19,CSC-1,PKT-E-16
DDA MARKET,SECTOR-8,ROHINI
DELHI,NORTH WEST DELHI-110085
GSTIN/UIN: 07BIHPA6624A1ZU
State Name : Delhi, Code : 07
Contact : +91-+91-9899090405

Invoice No. RFA/24-25/1686	Dated 26-Sep-24
Delivery Note	Mode/Terms of Payment
Reference No. & Date.	Other References
Buyer's Order No.	Dated
Dispatch Doc No.	Delivery Note Date
Dispatched through	Destination
Terms of Delivery	

Consignee (Ship to)
BASTI RAM YADAV
A-17 INDIRA ENCLAVE SOUTH DELHI IGNOU NEW DELHI
DL 110089
State Name : Delhi, Code : 07

Buyer (Bill to)
BASTI RAM YADAV
A-17 INDIRA ENCLAVE SOUTH DELHI IGNOU NEW DELHI
DL 110089
State Name : Delhi, Code : 07

Sl No.	Description of Goods	HSN/SAC	Quantity	Rate	per	Amount
1	AIS 140-R IRNSS VEHICLE LOCATION TRACKER DL1ZC2087 CH NO : B74227 E NO : 5174	85269190	1 NOS	5,500.00	NOS	5,500.00
	OUTPUT CGST @ 9%					495.00
	OUTPUT SGST @ 9%					495.00
	Total		1 NOS			₹ 6,490.00

Amount Chargeable (in words) E. & O.E
INR Six Thousand Four Hundred Ninety Only

HSN/SAC	Taxable Value	CGST Rate	CGST Amount	SGST/UTGST Rate	SGST/UTGST Amount	Total Tax Amount
85269190	5,500.00	9%	495.00	9%	495.00	990.00
Total	5,500.00		495.00		495.00	990.00

Tax Amount (in words) : INR Nine Hundred Ninety Only

Company's Bank Details
A/c Holder's Name : RAFFLE AUTOMOTIVE
Bank Name : ICICI BANK-082605002207
A/c No. : 082605002207
Branch & IFS Code : GHK & ICIC0000826
SWIFT Code :

Company's PAN : BIHPA6624A

Declaration
We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.

for RAFFLE AUTOMOTIVE
Authorised Signatory

This is a Computer Generated Invoice

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया, रायसीना रोड पर पेनिक बटन के नाम पर अरबो रुपये के घोटाले का पर्दाफास करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने मीडिआ को बताया कि दिल्ली में एक महिला मुख्य मंत्री बनी है और उनके मुख्यमंत्री बनते ही टैक्सी बसों वालो की दोबारा से मुसीबत आ गई है. महिलाओ की सुरक्षा के नाम पर पेहले से करोडो रूपए का भ्रस्टाचार हों रहा था. दिल्ली की नई मुख्य मंत्री बनते ही इनके परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली में 2019 मॉडल से पुरानी टैक्सी बसों में भी पेनिक बटन लगाना शुरू कर दिया गया है जिसको ये व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के नाम से टैक्सी बसों में लगा रहें है पेहले ये पेनिक बटन 2019 के मॉडल की टैक्सी बसों में लगने के आर्डर ही था. दिल्ली सरकार और दिल्ली का परिवहन विभाग महिलाओ की सुरक्षा के नाम पर काफी सालो से टैक्सी और बसों में में पेनिक बटन लगवा रहा हैं, ये पेनिक बटन नई टैक्सी बसों के रजिस्ट्रेशन के समय इन टैक्सी बसों में लगे हुए होने चाइये इसके बगैर इन टैक्सी बसों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली परिहवन विभाग में नहीं होगा. और इस पेनिक बटन के लिए हमारे टैक्सी बस वालो से से 7,000 रूपए से लेकर 16,000 रूपए तक लिए जा रहे हैं इसके लिए दिल्ली के परिवहन विभाग ने प्राइवेट वेंडर का एक पेनल बनाया हुआ हैं. ये पेनिक बटन किसी तरह से काम नहीं करता. एक तरह से ये टैक्सी बस वालो को लूटने का तरीका हैं. दिल्ली सरकार का परिवहन मंत्रालय और दिल्ली का परिवहन विभाग प्राइवेट कम्पनियो के साथ मिलकर एक बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा हैं. क्योंकि पैनिक बटन दबाने से कोई फायदा नहीं होता. अगर कोई महिला आपातकालीन समय में इस बटन को दबाकर आपके परिवहन विभाग से या पुलिस द्वारा साहयता लेना चाहे तो इसका कोई फायदा नहीं हैं क्योंकि इसके लिए कोई कॉल सेंटर आज तक दिल्ली के परिवहन विभाग ने नहीं बनाया हैं. एक तरह से ये मात्र 5 रुपए का पलास्टिक का बटन हैं जिसके लिए हमारे टैक्सी बस वालो से 7,000 रुपए से लेकर 16000 रूपए तक लिए जाते हैं दिल्ली मे टैक्सी बसो के फिटनेस के समय भी पेनिक बटन के नवनिकरण के नाम पर लगभग 8000 रुपए से 15000 रूपए तक जबरजस्ती वसूले जा रहे हे वो भी दिल्ली परिवहन मंत्रालय और दिल्ली परिवहन विभाग के पेनल मे प्राइवेट कम्पनियो के डीलरो द्वारा। वास्तव मे परिवहन मंत्रालय /दिल्ली परिवहन विभाग और प्राइवेट डीलरो की मिली भगत से ये सारा खेल चल रहा हे। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काफी सालो से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने काफी पत्र दिल्ली के उप राजयपाल, भारत के ग्रह राज्य मंत्री, भारत के परिवहन मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली परिवहन मंत्री को लिखें साथ ही दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को भी पत्र लिखें और इसके लिए हमने काफी मुलाक़ात ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और स्पेशल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी की लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ. हमने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल भी की .

हमने हमेशा पैनिक बटन की अनिवार्यता को तब तक के लिए हटाया जाए जब तक इसके लिए परिवहन विभाग कोई कॉल सेंटर नहीं बना देता. और परिवहन विभाग ने जितने पैसे पैनिक बटन के नाम पर टैक्सी बस वालो से लिए हैं वो पैसे टैक्सी बस वालो को ब्याज सहित वापिस किये जाए.

दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग के अनूसार इस पेनिक बटन के दबाने से उस इंसान की लोकेशन पता चल जाएगी और उस इंसान की तुरंत साहयता होंगी और इसका एक बड़ा कॉल सेंटर होगा ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी ने बोला था, और इसलिए दिल्ली सरकार ने पेनिक बटन की अनिवार्यता दिल्ली के टैक्सी बसों पर की हुई है, और सबसे बड़ी बात आज तक इसका कोई कॉल सेंटर नहीं है और दिल्ली के किसी भी पडोसी राज्य में ये पेनिक बटन टैक्सी बसों में नहीं लगाया जाता है.

एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना की इसकी शिकायत हम जल्दी भारत की महिला आयोग से भी करेंगे क्योंकी महिलाओ की सुरक्षा के नाम पर अरबो का घोटाला किया जा रहा है साथ ही प्रधान मंत्री जी और ग्रह मंत्री जी से इस मामले की जांच सीबीआई से भी करवाने के लिए लिखित शिकायत भी देंगे की किस तरह पैनिक बटन के नाम पर अरबो रुपए का घोटाला हुआ हैं.

अयोध्या ही नहीं बल्कि भारत के इन जगहों पर भी हैं फेमस राम मंदिर

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था। ऐसे में अयोध्या श्रीराम की जन्मभूमि होने के कारण वहां पर एक विशाल भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बता दें कि अयोध्या के अलावा भारत के अन्य हिस्सों में कई राम मंदिर मौजूद हैं।

अनन्या मिश्रा

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था। ऐसे में अयोध्या श्रीराम की जन्मभूमि होने के कारण वहां पर एक विशाल भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बता दें कि अयोध्या के अलावा भारत के अन्य हिस्सों में कई राम मंदिर मौजूद हैं।

भगवान श्रीहरि विष्णु इस जगत के पालनहार हैं। श्रीहरि ने धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए कई बार धरती पर अवतार लिया। वहीं भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले अयोध्यापति श्रीराम को लोग अपने भगवान व आराध्य के तौर पर पूजते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था। ऐसे में अयोध्या श्रीराम की जन्मभूमि होने के कारण वहां पर एक विशाल भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है।

ऐसे में अगले साल तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद साल 2024 में मकर संक्रांति के दिन श्रीराम लला की फिर से स्थापना की जाएगी। ऐसे में धार्मिक स्थल होने के कारण राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। अयोध्या में मौजूद राम मंदिर के बारे में तो हर कोई जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या के अलावा भारत के अन्य हिस्सों में कई राम मंदिर मौजूद हैं। कहा जाता है इन मंदिरों में पूजन-दर्शन से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं प्रभु श्रीराम को समर्पित इन मंदिरों के बारे में...

केरल का त्रिप्रायर मंदिर

केरल के त्रिशूर जिले में स्थित त्रिप्रायर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीराम की मूर्ति को स्थापित किया था। बाद में केरल के चेट्टुवा क्षेत्र में रहने वाले मछुआरे द्वारा इसको स्थापित किया गया। उसके बाद इस मूर्ति को वक्कायिल कैमल ने त्रिप्रायर में स्थापित किया। मान्यता के मुताबिक इस मंदिर में आने वाले भक्तों को बुरी आत्माओं से मुक्ति मिलती है।

नासिक का कालाराम मंदिर

महाराष्ट्र में नासिक के पंचवटी में भगवान श्रीराम को समर्पित कालाराम मंदिर स्थित है। इस मंदिर में श्रीराम की काले रंग की 2 फीट लंबी प्रतिमा मौजूद है। बताया जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान श्रीराम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रुके थे। कालाराम मंदिर का निर्माण सरदार रंगारू ओढेकर ने करवाया था। सरदार रंगारू ओढेकर ने एक रात गोदावरी नदी में श्री राम की एक काली मूर्ति होने का सपना देखा था। इसके बाद उन्होंने नदी से मूर्ति निकलवाकर मंदिर में स्थापित किया था।

तेलंगाना का सीता रामचंद्रस्वामी मंदिर

तेलंगाना के भद्रादी कोठागुडेम के भद्राचलम में सीता रामचंद्रस्वामी मंदिर स्थित है। मान्यता के अनुसार, लंका से माता सीता को वापस लाने के लिए भगवान श्रीराम ने गोदावरी नदी को पार किया था।

सीता रामचंद्रस्वामी मंदिर में श्रीराम के धनुष बाण के साथ त्रिभंगा रूप में स्थापित हैं।

एमपी का राम राजा मंदिर

मध्य प्रदेश के ओरछा में राम मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। यह ओरछा का इकलौता ऐसा मंदिर हैं, जहां पर श्रीराम की पूजा भगवान के तौर पर नहीं बल्कि राजा राम के तौर पर की जाती है। ओरछा के राजा राम को रोजाना गार्ड ऑफ ऑनर देकर शस्त्र सलामी दी जाती है।

तमिलनाडू का रामास्वामी मंदिर

बता दें कि तमिलनाडू का रामास्वामी मंदिर को दक्षिण भारत का अयोध्या कहा जाता है। यह दक्षिण भारत का एक ऐसा इकलौता मंदिर है। इस मंदिर में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की मूर्तियां स्थापित हैं।

प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं 3 फ्रूट्स ! तुरंत बना लें दूरी, वरना सेहत को होगा गंभीर नुकसान

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. प्रेग्नेंसी एक ऐसा पीरियड होता है, जिसमें महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं और उन्हें कई तरह के इंफेक्शन का खतरा ज्यादा होता है. प्रेग्नेंसी के दौरान सही डाइट लेना बेहद जरूरी होता है और जंक फूड्स से दूरी बनाने की जरूरत होती है. एक्सपर्ट गर्भवती महिलाओं को अलग-अलग समय पर अपने खान-पान में कुछ बदलाव करने की सलाह देते हैं. दरअसल गर्भ में पल रहे बच्चे को सही पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ताकि उसका विकास सामान्य तरीके से हो. अगर प्रेग्नेंसी के दौरान गर्भवती महिलाएं सही डाइट नहीं लेंगी, तो उसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ पर होगा. इसी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें डॉक्टर्स से जान लेते हैं.

इस बारे में दिल्ली के फोर्टिस ला फेम हॉस्पिटल के ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. सुप्रिया कहती हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने खानपान का खास ध्यान रखना चाहिए. पहले तीन महीने में पपीता, अनानास और एवाकाडो जैसे फ्रूट्स का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से उनकी सेहत और गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है. प्रेग्नेंसी के तीन महीने के बाद महिलाओं को पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिससे उन्हें अधिक मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन और मिनरल्स मिलें. महिलाओं को दूध, दही, पनीर, फ्रूट, हरी सब्जियां, दालें, सोया, टोफू अधिक मात्रा में लेना चाहिए. इसके अलावा नॉन वेज खाने वाली महिलाओं को अंडा, फिश, चिकन का हफ्ते में दो दिन सेवन करना चाहिए. इससे प्रेग्नेंसी और उसके बाद भी महिला और शिशु स्वस्थ रहेंगे.

प्रेग्नेंट महिलाओं की लाइफस्टाइल और सावधानियों को लेकर फोर्टिस ला फेम हॉस्पिटल के ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की एडिशनल डायरेक्टर डॉ. जूही जैन कहती हैं कि प्रेग्नेंट होना महिलाओं के लिए प्रकृति का सबसे सुखद अहसास है और इसे महसूस करना चाहिए. गर्भवती महिलाएं प्रेग्नेंसी के दौरान घर का बना ताजा खाना खाएं और प्रोटीन, हरी सब्जियों और फलों का सेवन जरूर करें. फास्ट फूड, जंक फूड और बाहर के खाने से दूर रहें. दिनभर एक्टिव रहें और ज्यादा से ज्यादा टहलें. प्रेग्नेंसी के चार महीने बाद महिलाएं योग कर सकती हैं. डॉक्टर की सलाह पर ब्लड, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाएं. ब्लड प्रेशर लगातार चेक करवाते रहें. प्रेग्नेंट महिलाएं जरूरी वैक्सीन अवश्य लगवाएं. फोलिक एसिड की गोली प्रेग्नेंसी के पहले तीन महीने में लेना जरूरी है. अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएं और डॉक्टर के संपर्क में रहें.

पश्चिम भी स्वीकार रहा है कि सुख-दु :ख वास्तव में भौतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करते

शिवेश प्रताप

आज पश्चिमी मनोविज्ञान इस स्थिति में पहुंचा जहाँ दबे स्वर में स्वीकारा जा रहा कि सुख-दु :ख वास्तव में भौतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करते। सुख-दु :ख मनुष्य की अनुभूति के ही परिणाम हैं, उसकी मान्यता, कल्पना एवं अनुभूति विशेष के ही रूप में सुख-दुख का स्वरूप बनता है।

रामचरितमानस एक ओर राम का जीवन चरित्र व मनुष्य जाति के अनुभवों का उत्कट निचोड़ है तो दूसरी ओर यह 'नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद्' होकर सनातन धर्म के सभी मानक ग्रंथों के अर्क स्वरूप भी है, जिसे मानस के अंत में 'छहों शास्त्र सब ग्रन्थन को रस' कह कर दोबारा पुष्ट कर दिया गया है। मनुष्य से पुरुषोत्तम बनकर यानि मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ने की यात्रा के पथ प्रदर्शक श्रीराम हैं। अपने भीतर छिपी संभावना और सुख-शांति की अभीप्सा को पूरा कर सकने की आकांक्षा के बीच, रामचरितमानस में राम इस मार्ग का संकेत हैं कि मनुष्य के स्वरूप को चरितार्थ करने और उससे ऊपर उठने और अपने भीतर निहित संभावनाओं को साकार करने का कोई लघुमार्ग (शॉर्टकट) नहीं हैं।

पारिवारिक, सामाजिक और लौकिक जीवन के कर्तव्य परायणता में राम ने अपने आचरण और व्यवहार से जो मानक स्थापित किए, उन मानकों में यह संभावना हमेशा निहित रही कि व्यक्ति का व्यवहार, परिस्थिति के अनुसार भले बदलता रहे, लेकिन उसका अंतरंग स्थिर रहे। मानव उन्हीं मूल्यों का प्रतिनिधित्व करे जो शाश्वत हो, जो मनुष्य और समाज के लिए हमेशा उपयोगी और ऊंचा उठाने वाले हों। उदाहरण के लिए परिवार को ही लें, राम में परिवार के अनुशासन, सबके प्रति विश्वास, एक-दूसरे के सुखों और इच्छाओं का निर्वाह और उनके लिए त्याग की भावना का महत्व रहा है। इन मूल्यों का निर्वाह रामचरित के हर प्रसंग में होता दिखाई देता है। क्षण भर में राजमुकुट धारण कर राजा राम बनने वाले बनवासी राम बनने हेतु बल्कल वस्त्र पहन लेते हैं और पिता के वचनों एवं माता कैकेयी के प्राप्त वरदान हेतु वन जाने हेतु निकल जाते हैं।

व्यक्तिगत जीवन में राम ने एक ओर मर्यादाओं की प्रतिष्ठा की तो दूसरी ओर उन्होंने जहां जरूरी समझा, वहां मान्यताओं में दखल भी दिया। शूर्पणखा का अंग-भंग, अहिल्या को पुनर्जीवन और प्रतिष्ठा, एक पत्नीव्रत, बाली उद्धार, शबरी उद्धार, विभीषण को लंका का राज दे देना आदि कई प्रसंग हैं, जिनमें वह परंपरा से हटकर काम करते हैं। यह सब करते हुए वह धर्म-मर्यादा की स्थापना ही कर रहे होते हैं क्योंकि मर्यादा की स्थापना ही धर्म की शाश्वतता को बनाये रखती है। यदि यज्ञाग्नि भी मर्यादा का उल्लंघन करे तो उसे जल के द्वारा नियंत्रित करने का विधान धर्म का ही है। यदि इन कामों को पारिवारिक और सांस्थानिक रचनाओं के भरोसे छोड़ा जाता तो संभवतः पंचायतें, न्यायालय, दंडाधिकारी और समितियों को उन नतीजों पर पहुंचने में वर्षों लग जाते और न्याय की प्रक्रिया संपन्न होते- होते वह अर्थहीन व अनुपयोगी हो जाते।

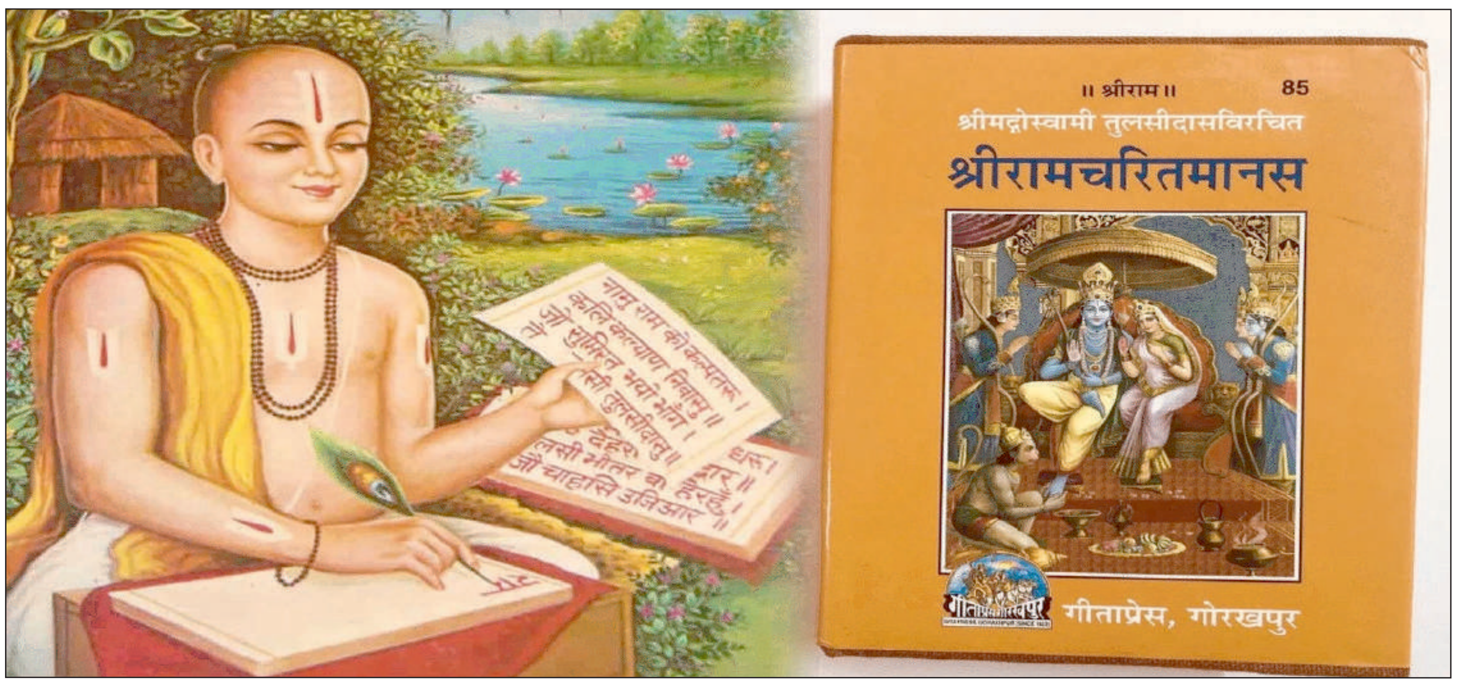

टूटते संयुक्त परिवारों का सहारा है राम परिवार

इन दिनों परिवार का ढांचा बदल रहा है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। कई जगह तो नौकरी के कारण पति-पत्नी और बच्चों के लिए भी अलग तरह से सोचना और व्यवस्था बनानी पड़ रही है। ऐसे में जब कि ज्ञान परम्परा का एक पीढ़ी से दूसरी में प्रवाह बाधित हो गया है तो राम का चरित्र, मूल्य, व्यवहार और आदर्शों की यशोगाथा को समेटे श्री रामचरितमानस/ रामायण जीवन का संविधान बन सकता है। आज के बड़े-बड़े फैमिली सलाहकार अपनी सलाह में परिवारों में यही अंतिम सत्य बताते हैं कि परिवार वह इकाई है जहाँ आप तर्कों और जय-पराजय से समाधान नहीं पा सकते अपितु त्याग के द्वारा कर्तव्य पालन करके ही सुख शांति प्राप्त करेंगे। यह मान्यता भारत में त्रेतायुग में ही प्रभु राम के जीवन से स्थापित हो चुकी थी।

राम परिवार के आदर्श-स्नेह, सहयोग, सद्भाव और विश्वास को आधार बनाकर आपसी संबंधों, कर्तव्यों और दायित्वों को समझा और निबाहा जा सकता है। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास संपन्न कर अयोध्याजी वापस आते हैं तो माता कौशल्या ने मिलते ही सबसे पहले लक्ष्मण से आकुल होकर पूछा कि मुझे दिखाओ तुम्हें शक्ति कहाँ लगी थी, पुत्र तुम्हें कितनी वेदना से गुजरना पड़ा ! लक्ष्मण जी ने इसका उत्तर दिया, 'वेदना राघवेन्द्रस्य केवलं व्रणिनो वयम' (वाल्मीकि रामायण) अर्थात हमें तो केवल घाव हुआ था, वेदना तो बड़े भाई राम को हुई थी। बस यही राम का सार है की सभी एक- दूसरे के भाव, प्रेम, हर्ष और विषाद में एकरस हो जाएँ।

राम जी के छोटे भाई भरत जी का चरित्र तो ऐसा है की कहीं-कहीं उनकी श्रद्धा, समर्पण और मर्यादा रूपी हिमालय के आगे रामजी लघु प्रतीत होते हैं। भाई की चरण पादुका से राज चलाना और स्वयं नंदीग्राम में भूमि पर सोना और पर्णकुटी में रहना। राम जी अपने भाई भरत को राजधर्म की सीख देते हुए कहते हैं की, 'मुखिआ मुखु सो चाहिए' यानि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो स्वयं के पोषण या सुख में अकेला है, परन्तु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन-पोषण करता है। राम और भरत का चरित्र भरत-मिलाप प्रसंग में एक दूसरे के सामने ऐसे अडिग हैं की तुलसीदास जी को लिखना पड़ता है 'धीर धुरंधर धीरजु त्यागा' यानि भरत जी के असीम त्याग और मर्यादा के समक्ष धैर्य की धुरी धारण करने वाले श्रीराम को भी अपना धीरज प्रेमाश्रुओं के सामने तोड़ देना पड़ता है।

अयोध्या के एक राजकुमार श्री राम द्वारा सुदूर वन में हनुमान को आभार व्यक्त करने के क्रम में कहा जाता है- मय्येव जीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतं हरे। नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमनुकाङ्क्षति ॥ (हे कपिकुलनन्दन।) आपने जो मेरे साथ उपकार किया है वह मेरे में ही जीर्ण हो जाय (मुझमें पच जाय), बाहर अभिव्यक्ति का कोई अवसर ही न आवे, क्योंकि प्रत्युपकार करने वाला व्यक्ति अपने उपकारी के लिये विपत्ति की कामना करता है, जिससे उसे अपने प्रत्युपकार के लिए उचित अवसर मिले (वा. रामायण)।

भगवान राम के समय में सनातन संस्कृति के वैचारिक मानदंडों पर विचार करें और उस काल खंड में संसार की अन्य संस्कृतियों के विकास से तुलना करें तो सहज ही आपको यह अनुभव होगा कि राम और अयोध्या के समाज का उत्कृष्ट सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्य कितना ऊँचा था और संसार भर में क्यों प्रासंगिक हुआ।

सुख-दुःख की अनुभूति

आज पश्चिमी मनोविज्ञान इस स्थिति में पहुंचा जहाँ दबे स्वर में स्वीकारा जा रहा कि सुख-दुःख वास्तव में भौतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करते। सुख-दुःख मनुष्य की अनुभूति के ही परिणाम हैं, उसकी मान्यता, कल्पना एवं अनुभूति विशेष के ही रूप में सुख-दुख का स्वरूप बनता है। जैसा मनुष्य का भावना स्तर होगा उसी के रूप में सुख-दुःख की अनुभूति होगी। एक ओर जहाँ पश्चिमी संसार सुख को परिभाषित करने में भौतिक संसाधनों के अंतहीन दौड़ में लगा है वहीं सनातन धर्म में सुख-दुःख का विमर्श एक साथ त्रेतायुग से होता आया है। हम मानते हैं कि सुख और दुःख दो भिन्न अवस्थाएं होते हुए भी एक-दूसरे के पूरक हैं।

मृत्युशैय्या पर पड़े हुए दशरथ से मंत्री सुमंत्र कहते हैं-

जनम मरन सब दुख सुख भोगा। हानि लाभु प्रिय मिलन बियोगा ॥
काल करम बस होहि गोसाई। बरबस रात्रि दिवस की नाई।
सुख हरषहिं जड़ दुख बिलखाहीं। दोड सम धीर धरहिं मन माहीं ॥

अर्थात जन्म-मरण, सुख-दुःख के भोग, हानि-लाभ, प्यारों का मिलना-बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी, काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुःख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। (मानस)

श्रीराम, कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता

भगवान श्रीराम एवं उनके समाज का चिंतन केवल रावण को मारकर सीता माता की प्राप्ति तक सीमित कर देना उचित नहीं है, जैसा कि आज के डिजिटल विमर्श में चहुंओर दिखाई दे रहा है। आज जबकि भारतीय समाज एकजुट होकर श्री अयोध्या जी में प्रभु राम का भव्य मंदिर बना रहा है तो ऐसे में हम सभी को समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यानि अपने परिवार के प्रबोधन पर विशेष बल देना चाहिए। ऐसे में राम के सामाजिक, पारिवारिक एवं कर्त्तव्य आधारित चिंतन का परिवार के साथ प्रतिदिन 10 मिनट बैठकर विमर्श अवश्य करना चाहिए। बच्चों को अगले दिन राम के ऊपर बोलने का चिंतन बिंदु दें जिससे उनके भीतर भी संस्कार की ज्योति जल सके। घर में एक रामचरितमानस रखें और सप्ताह में एक बार पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसका पाठ अवश्य करे।

-शिवेश प्रताप

(लेखक शिवेश प्रताप, धर्म-संस्कृति के अध्येता हैं तथा प्रभुराम के डिजिटल विश्वकोश RamCharit.in के फाउंडर हैं।)

बस मार्शलों को फिर बहाल करने के लिए विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र गुरुवार से शुरू हुआ। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला सत्र है। सदन के शुरू होते ही पहले सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष ने काफी हंगामा किया। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक कुलदीप कुमार ने सत्र में उठाए गए मुद्दों के बारे में आईएएनएस से बात की।कुलदीप कुमार ने बताया कि आज सत्र में सबसे पहला मुद्दा दिल्ली के बस मार्शलों का उठा।दिल्ली में हमारी बहन-बेटियों की सुरक्षा करने वाले बस मार्शलों को दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक झटके में नौकरी से निकाल दिया। इस मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए आज सदन में चर्चा हुई जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया है कि 3 अक्टूबर को विपक्ष और सत्तापक्ष के विधायक उपराज्यपाल कार्यालय जाएंगे और मार्शलों को उनकी नौकरी वापस दिलाई जाएगी, "जो एलजी ने साजिश के तहत छीन ली है"।

उन्होंने कहा, "दिल्ली के 1,100 पेड़ों को काटकर पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम दिल्ली के उपराज्यपाल ने किया है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। जिस तरह से एलजी ने सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर तानाशाही के बल पर पेड़ों को काटा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा फटकार लगाता रहा है।"

आप विधायक महेंद्र गोयल ने आईएएनएस से कहा कि आज इस सत्र में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, जिसमें दिल्ली में तैनात बस मार्शलों को हटाने का मुद्दा भी शामिल है। इस संबंध में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। अब बस मार्शलों को फिर से बहाल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल आ गए हैं और दिल्ली की जनता के काम रोकने का जो काम भाजपा करती आ रही है, उन कामों को अब फिर से शुरू किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में नया मुख्यमंत्री बनने के बाद आज से विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में जमानत पर रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज सदन में भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ३पीएम मोदी भगवान नहीं हैं३। कुर्सी से चिपके रहना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने उपराज्यपाल पर भी दिल्ली के विकास को रोकने का आरोप लगाया।

दिल्ली विधानसभा का सत्र हंगामे के साथ शुरू,पक्ष मार्शल के मुद्दे पर तो विपक्ष CAG पर चाहता है चर्चा

दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय सत्र शुरू हुआ। बतौर मुख्यमंत्री आतिशी का ये पहला सत्र है। दिल्ली में अगले साल की शुरूआत में चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष मार्शल के मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहती है तो वहीं विपक्ष CAG रिपोर्ट पर चर्चा ताहती है। सदन में AAP-BJP के बीच हंगामा हो रहा है।

नई दिल्ली। विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बृहस्पतिवार से शुरू हुआ। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला सत्र है। सदन के शुरू होते ही पहले सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष ने काफी हंगामा किया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने बस मार्शलों के समर्थन में नारेबाजी की। आप विधायक कुलदीप कुमार ने हंगामा किया। बाद में उनके समर्थन में बाकी आप के विधायक खड़े हो गए। स्पीकर रामनिवास गोयल ने 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर हंगामा होने लगा। विपक्ष के विधायक कैग रिपोर्ट पेश करने के नारे लगाते दिखे। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रेसवार्ता में कहा कि दो दिवसीय विधानसभा सत्र का एजेंडा क्या है, इस बारे में विधायकों को कोई जानकारी नहीं दी गई। दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के कारण इस बार मानसून में कई लोगों की मौत हो गई। झुग्गियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन, प्रदूषण की समस्याओं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलने, केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं करने, सहित अन्य मुद्दों को भी उठाया जाएगा।

"यह 10000 बस मार्शल अब बर्बादी की कगार तक पहुंचे गए हैं जल्द से जल्द उनकी बहाली की जाए"

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में सदन को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि दिल्ली के लगभग 10000 बस मार्शल आज बर्बादी की कगार पर आ गए हैं I उन्होंने कहा कि आज इन 10000 बस मार्शलों के घर में चूल्हा जलना बंद हो गया है, जो लोग किराए पर रह रहे हैं वह अपने घर का किराया तक नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लोगों ने परेशान होकर आत्महत्या तक कर ली है और बेहद ही परेशानियों में यह लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं I उन्होंने कहा इनमें से अधिकतर लोग बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं और ज्यादातर अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले हैं I उन्होंने कहा कि इन 10000 बस मार्शलों के जरिए से दिल्ली की बसों में चलने वाली महिलाओं को एक बेहतर सुरक्षा मुहैया कराई जा रही थी, परंतु अब वह बंद हो चुकी है I

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बसों में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है, बदतमीजी की जाती है और इसी प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली की बसों में बस मार्शलों को तैनात किया गया था, ताकि बसों में चलते वक्त महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, और उन्हें पता हो कि यदि कोई भी उन्हें परेशान करता है तो यहां कोई ऐसा है, कि जिसे वह शिकायत कर सकती हैं I उन्होंने कहा कि यह सभी बस मार्शल अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, सब कुछ बेहतर चल रहा था और अचानक से जनवरी 2023 में इन बस मार्शलों की तनख्वाह रोक दी गई I मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब से दिल्ली में उपराज्यपाल के पद पर विनय सक्सेना आए हैं, एक पैटर्न सेट कर लिया गया है, कि जिस विभाग को भी बर्बाद करना हो उस विभाग द्वारा बनाई गई योजनाओं में कुछ ना कुछ कमी निकालकर उसे बंद कर दिया जाए I मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दुनिया की कोई भी योजना हो यदि ढूंढा जाए तो उसमें एक कमी तो निकाली ही जा सकती है I बस इसी का सहारा लेकर दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों द्वारा जनहित में बनाई गई योजनाओं को रोकने का काम किया जा रहा है I

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अधिकारियों को इस प्रकार की योजनाओं को रोकने के लिए निर्देश दिए जाते हैं और अधिकारी उस योजना में कोई भी छोटी-मोटी कमी निकालकर उसको रोकने का काम शुरू कर देते हैं I इसी पैटर्न के तहत ट्रांसपोर्ट विभाग के एक अधिकारी आशीष कुंद्रा जो कि उपराज्यपाल महोदय का चाहिता अधिकारी हैं, उनको भी दिल्ली की बसों में तैनात किए गए बस मार्शलों की इस योजना को रोकने का काम दिया गया I उन्होंने कहा कि यह बड़े-बड़े अधिकारी अपने विभाग के छोटे क्लर्क ग्रेड एवं एसओ स्तर के अधिकारियों को निर्देश देते हैं और वह अधिकारी उस योजना की फाइल में लिख देते हैं, कि यह योजना ठीक नहीं है, उसके पश्चात उच्च अधिकारी तक उस नोटिंग को हस्ताक्षर करके अप्रूव कर देते हैं और योजना बंद कर दी जाती है I मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ऐसा ही एक नोट बस मार्शलों की योजना को रोकने के लिए उनकी फाइल पर भी लिख दिया गया I उन्होंने कहा की फाइल में लिखा गया क्योंकि बसों में सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं, पैनिक बटन लगा दिया गया है तो अब इन बस मार्शलों की कोई आवश्यकता नहीं है I मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि फाइल पर लिखे गए इस नोटिंग से ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री कैलाश गहलोत एवं राजस्व विभाग की मंत्री अतिशी दोनों ही असहमत थे, परंतु फिर भी उनकी असहमति को दरकिनार कर अधिकारियों द्वारा इस फाइल को अप्रूव किया गया और जनवरी 2023 में बस मार्शलों की तनख्वाह रोक दी गई I

इस मामले में उस समय के तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि जनवरी में इन बस मार्शलों की तनख्वाह रोके जाने के बाद जब सितंबर के माह तक उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई तो यह मामला गरमाया और इसका संज्ञान लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल महोदय को लिखा, कि इन सभी बस मार्शलों को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए और उनकी तनख्वाह जल्द से जल्द इन लोगों को दी जाए I साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी लिखा कि जिन अधिकारियों ने इन गरीब बस मार्शलों की तनख्वाह रोकने का काम किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए I अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकार के अधिकारी केवल अपनी तनख्वाह और अपने प्रमोशन से ही मतलब रखते हैं, किसी गरीब आदमी की समस्याओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं है I सदन के माध्यम से प्रश्न पूछते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने इस मामले में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की?

उन्होंने कहा की 29 फरवरी 2024 को इस सदन के पटल पर एक संकल्प पत्र रखा गया था इन बस मार्शलों की बहाली के संबंध में और आज हम इस सदन के पटल पर एक बार फिर से एक संकल्प पत्र रख रहे हैं और जैसा की भाजपा के विधायक गणों की ओर से जो सुझाव है, उन सुझावों को इस संकल्प पत्र में शामिल करते हुए, दिल्ली सरकार के सुझावों को भी उसमें सम्मिलित कर उपराज्यपाल महोदय को भेजा जाएगा I सदन के माध्यम से मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भाजपा के सभी विधायकों के सम्मुख प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इस प्रकार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला बहुत हो चुका है, आज हम इस सदन के पटल से इस बात का एलान करते हैं, कि 3 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री उपराज्यपाल महोदय से, इस संबंध में मिलने के लिए तैयार हैं और हम आशा करते हैं, कि भाजपा के सभी विधायक गण भी हमारे साथ उपराज्यपाल महोदय के कार्यालय चलेंगे और जब तक इस मामले पर उपराज्यपाल महोदय की ओर से कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक उनके कार्यालय से नहीं आएंगे I साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उपराज्यपाल महोदय जहां जिस पेपर पर इन बस मार्शलों की बहाली के संबंध में जो लिखने के लिए कहेंगे, जहां हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के मंत्री वहां हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, परंतु इन बस मार्शलों की बहाली जल्द से जल्द होनी चाहिए I सदन के माध्यम से मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उपराज्यपाल महोदय इस संबंध में अब भी कोई कार्रवाई नहीं करते तो यह साफ हो जाएगा कि इन बस मार्शलों की बहाली को रोकने का काम भाजपा और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उपराज्यपाल महोदय द्वारा किया जा रहा है I

इसके बाद सभी के सहमति से सदन में प्रस्ताव पास हुआ कि हमारे ओर भाजपा के सभी विधायक और सरकार के मंत्री 3 अक्टूबर 2024 को उपराज्यपाल कार्यालय जाएँगे।

'जब तक सफाई नहीं, तब तक काउंटिंग नहीं'
DUSU चुनाव परिणाम पर दिल्ली HC का अनोखा आदेश

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU Election 2024 पर बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा दिया है। चुनाव कैंपेन के दौरान जिस तरह से विश्वविद्यालय के कॉलेजों में गंदगी की तस्वीरें आई थीं उसका संज्ञान लेते हुए बुधवार को हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी। अब गुरुवार को हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को चुनाव की इजाजत तो दे दी है लेकिन वोटों की गिनती पर तब तक के लिए रोक लगा दी...

नई दिल्ली। DUSU ELECTION के कैंपेन के चलते विश्वविद्यालय में पर्चों, पैंफलेट आदि से हुई गंदगी की तस्वीरें सामने आईं थीं, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाया है।

अदालत ने विश्वविद्यालय को चुनाव कराने की अनुमति तो दे दी है लेकिन वोटों की काउंटिंग पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि विश्वविद्यालय प्रशासन कोर्ट को यह विश्वास न दिला दे दी कैंपस पूरी तरह से साफ हो चुका है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई ये शर्तें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डीयूएसयू) चुनाव जारी रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण शर्त लगा दी है।

कोर्ट ने कहा है कि जब तक यूनिवर्सिटी अदालत को संतुष्ट नहीं कर देती कि सभी पोस्टर, होर्डिंग्स, भित्तिचित्र और अन्य अभियान-संबंधी सामग्री हटा दी गई है और सार्वजनिक संपत्ति बहाल कर दी गई है, तब तक वोटों की गिनती नहीं होगी।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और मतपेटियों को अगला आदेश जारी होने तक सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाना चाहिए।

शाही ईदगाह के मुद्दे पर कानून व्यवस्था बनाए रखें: डॉ. सरदार खान

सुषमा रानी

नई दिल्ली: शाही ईदगाह के मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सरदार खान का कहना है कि इस मुद्दे पर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और आगे सुनवाई चल रही है, इसलिए सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करें और शांति बनाए रखें. क्षेत्र. व्यवस्था बनाए रखें और धैर्य दिखाएं.

शाही ईदगाह के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बयान पर आपत्ति जताते हुए डॉ. सरदार खान ने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मी बाई के व्यक्तित्व और उनके बलिदान से न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व परिचित है और देश का बच्चा-बच्चा उनके सम्मान को समझता है। ऐसे लोगों के नाम पर बंटवारे की राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति क्यों की जाती है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस लड़ाई में नहीं घसीटा जाना चाहिए. कोर्ट ने तय कर दिया है कि रानी झाँसी की मूर्ति कहाँ स्थापित की जानी चाहिए और अब कोर्ट के फैसले के बाद कुछ भी कहना संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है। क्या इस मामले पर बोलने वालों को नहीं पता कि कल कोर्ट का फैसला आया है और उन्होंने कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर अपना फैसला क्यों दिया. डॉ. सरदार खान ने कहा कि मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वे किसी के बहकावे में न आएं और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शांति बनाए रखें.

मुझे गिरफ्तार करने के पीछे उनका मकसद दिल्लीवालों को तकलीफ पहुंचाना और "आप" सरकार को बदनाम करना था- केजरीवाल

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं। गुरुवार को उन्होंने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री आतिशी और विधायक दिलीप पांडे के साथ तिमारपुर विधानसभा स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय सड़क का दौरा कर जायजा लिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने साजिश के तहत मुझे जेल भेजकर दिल्ली के काम रोक दिए थे। लेकिन अब मैं जेल से बाहर आ गया हूं। दिल्ली की जनता चिंता ना करे। अब मैं दिल्ली का कोई भी काम रूकने नहीं दूंगा और रूके हुए सभी काम जल्द पूरे कराए जाएंगे। इसी के मद्देनजर आज मैंने मुख्यमंत्री आतिशी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सड़क का निरीक्षण किया। इस सड़क को जल्दी ठीक किया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली की बाकी सड़कों को भी जल्द ठीक कराया जाएगा।

विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के सामने से गुजर रही सड़क पर खासकर पीक ऑवर्स के दौरान ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। यह सड़क जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। निरीक्षण के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्थानीय विधायक दिलीप पांडे से उनके विधानसभा क्षेत्र की अन्य टूटी सड़कों के बारे में भी जानकारी ली। विधायक ने बताया कि एक और सड़क है, जिसकी मरम्मत जरूरी है। इसके अलावा, एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में कुछ सड़कें हैं, जिनकी मरम्मत के लिए कार्य आवंटन की प्रकिया चल रही है। करीब 36 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 30 की स्वीकृति हो चुकी है।

इस दौरान मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दो-चार दिन पहले मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनसे मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा मिला? उस नेता का जवाब सुनकर मैं बहुत भौचक्का रह गया। उस नेता ने मुझे बताया कि आपको गिरफ्तार करने से दिल्ली सरकार तो पटरी से उतर ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुनकर बहुत दुख हुआ और बहुत तगड़ा शॉक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद केवल दिल्ली को ठप करना था। क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली सरकार को पटरी से उतारना था। क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद दिल्लीवालों को तकलीफ पहुंचाना और दिल्ली के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करना था।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से कहा कि अब मैं आ गया हूं, आप चिंता न करें। आपके जितने भी रूके हुए काम थे, वो दोबारा शुरू होगे। जितनी समस्याए हैं, उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग डीयू के नार्थ कैंपस के सामने से गुजर रही सड़क का जायजा लेने के लिए आया थे। इस सड़क के नीचे पानी की पाइप लाइन पड़ी है। इस पाइप लाइन की वजह से सड़क टूट गई है। लोगों द्वारा इस सड़क को काफी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने मुख्यमंत्री आतिशी से इस सड़क की मरम्मत को लेकर बात की है। अब इस सड़क को जल्द ही ठीक कराया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली के अंदर जो भी सड़कें टूटी हैं, उनका हम लोग मुआयना करेंगे और उनकी मरम्मत कराएंगे।

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों का मकसद ही था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना था। लेकिन हम दिल्ली के लोगों का काम रूकने नहीं देंगे। अब मैं जेल से बाहर आ गया हूं। अब सभी रूके हुए काम दोबारा चालू होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा एक्शन मोड में थी, मैं जेल में भी एक्शन मोड में था।

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने मुझे जेल भेजकर दिल्ली के काम रोक दिए थे। सड़कें भी ख़राब हो गईं। उनका यही मक़सद था। आज मैंने मुख्यमंत्री आतिशी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सड़क का निरीक्षण किया। इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। दिल्ली की बाक़ी सड़कों को भी जल्द ठीक कराया जाएगा। अब मैं वापस आ गया हूं, दिल्ली के लोग चिंता न करें। दिल्ली के सभी रूके हुए काम कराएंगे।

उधर, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ट्वीट कर कहा कि आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ विश्वविद्यालय मार्ग की सड़क का निरीक्षण किया। सड़क बहुत जर्जर हाल में है। इसको जल्द बनाया जाएगा। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिल्ली को ठप करने की साज़शि रची थी। लेकिन दिल्लीवालों के बेटे अरविंद केजरीवाल अब फिर जनता के बीच में हैं, उनके मार्गदर्शन में दिल्ली के रुके काम दोगुनी गति से पूरे होंगे।

कविता : भैंस हुई गिरफ्तार !

तीन लोक से न्यारी नगरी मथुरा में,
अब हुआ है भई कुछ नया।
वृंदावन के संरक्षित कुंभ मेला क्षेत्र में,
एक अपनी भैंस चराने गया।
भैंसों को भी हरे पत्ते खाकर मजा आया,
नहीं पता था इसकी मिल जाएगी सजा।
ज़ब नगर निगम का ध्यान उस पर गया।
हरे पत्ते खाने पर अधिकारियों के,
माथे पर ही ऐसे बल पड़ गया।
अभी-अभी तो पौधारोपण कर,
हमने सब कुछ हरा-भरा कर दिया।
अधिकारियों ने ऐसी पकड़ी रफ्तार,
पहली बार भैया भैंस हुई गिरफ्तार।
इस घटना से जिले में खूब हो रहीं चर्चा,
भैंस का मालिक फंस गया है।
उस पर तो ज़बरदस्त धाराएं लग गई है।
अधिकारियों के चक्कर काट रहा।
लगता है उसका खूब होगा खर्चा।
अब तक तो जाती थी भैंस पानी में।
हरे पत्ते खाने से भैंस पहुँची थाने में।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)

NH9 पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बोला धावा, लगी वाहनों की लंबी कतार; राहुल गांधी से जुड़ा है मामला

परिवहन विशेष न्यूज

ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश है। गुरुवार को ओबीसी कार्यकर्ता राहुल गांधी का घेराव करने के लिए लेकिन पुलिस ने उन्हें यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं को रोकने में पुलिस अधिकारियों के पसीने छूट गए और वाहनों को डायवर्ट करना पड़ा। इससे वाहनों चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

साहिबाबाद (गाजियाबाद)। यूपी के गाजियाबाद में ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी को लेकर गुस्सा है। ओबीसी मोर्चा OBC Morcha के कार्यकर्ता गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास का घेराव करने जा रहे थे, इसी बीच उन्हें यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया गया।

इस दौरान हाईवे पर लंबा NH9 Jam जाम लग गया है, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम लगने से काफी संख्या में लोग जाम में फंस गए हैं। वहीं, NH9 और NH58 समेत कई मार्गों पर NH58 Jam जाम लगा हुआ है। जाम को खुलवाने में पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं।

वहीं, पुलिस ने खोड़ा के पास एनएच-9 पर बैरियर लगाकर वाहनों को रोका गया है। एनएच नौ पर दिल्ली जाने वाली लेन और सर्विस रोड पर लंबा जाम लग गया है।

मंत्री नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में हो रहा प्रदर्शन

BJP Wokers Protest वहीं, प्रदर्शन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री व ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सर्विस लेन पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। वाहनों को डाइवर्ट कर फ्लाईओवर के ऊपर से दिल्ली भेजा जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में यूपी गेट पर कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं।

पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया

इस दौरान पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए ओबीसी मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उन्हें गाड़ी में बैठाकर ले गई है। वहीं, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है।

नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष को हिरासत में लिया

वहीं, पुलिस ने खोड़ा नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उन्हें गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गई है।

बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश

पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दिए हैं। हालांकि, कार्यकर्ताओं को रोकने में पुलिस अफसरों के पसीने छूट गए हैं। इस दौरान त्रिपुरा स्टेट फोर्स के जवान बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकते हुए दिखे।

बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश

पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैरियर तोड़कर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश की। इस दौरान प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करते दिखें।

बीड़ी पीने से मना करने पर 13 साल का छात्र आगबबूला, मौलाना का आरी से गला रेता

एक 13 वर्षीय छात्र ने मौलाना आस मोहम्मद का गला आरी से रेत दिया। छात्र को मौलाना ने बीड़ी पीने से मना किया था। गुस्से में छात्र ने देर शाम मदरसे में जाकर सो रहे मौलाना पर हमला कर दिया। मौलाना को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने छात्र को हिरासत में ले लिया है।

गाजियाबाद। मोदीनगर के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव त्योडी-13 बिस्वा में पिटाई से गुस्सा छात्र ने मौलाना का आरी से गला रेत दिया। गंभीर हालत में मौलाना को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। पुलिस अपने स्तर से जांच में जुटी है। भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव त्योडी-13 बिस्वा में मदरसा हैं, जहां 8वीं कक्षा तक पढ़ाई होती हैं। यहां कक्षा छह में गांव का ही 13 वर्षीय किशोर पढ़ाई करता है। दो दिन पहले वह कक्षा में बीड़ी पी रहा था।

छात्र के बीड़ी पीने से मौलाना ने जताई आपत्ति

ऐसा करते देख मौलाना आस मोहम्मद ने देखा। उन्होंने छात्र को टोका और पिटाई कर दी। दोबारा से बीड़ी नहीं पीने की चेतावनी दी। छात्र इसी बात से भड़क गया। देर शाम वह मदरसे में गया और कमरे में सो रहे आस मोहम्मद का गला आरी से रेत दिया। उनकी चीख पुकार सुनकर अन्य लोग दौडे और अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना पर पुलिस (Ghaziabad Police) भी मौके पर पहुंची। छात्र को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मौके से खून से सनी आरी मिली है। मौलाना के परिवार की तरफ से कोई शिकायत अभी नहीं दी गई है। एसीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि मौलाना अस्पताल में उपचारधीन हैं। उनकी हालत खतरे से बाहर है। मामले में जांच की जा रही है।

लोनी में ई-स्कूटी की फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां

लोनी के ट्रॉनिका सिटी में स्थित एक ई-स्कूटी और ई-रिक्शा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है लेकिन शॉर्ट-सर्किट की आशंका जताई जा रही है। फैक्ट्री में करीब 50 लोग काम करते थे लेकिन आग लगने के समय सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची।

परिवहन विशेष न्यूज

साहिबाबाद (गाजियाबाद)। यूपी के गाजियाबाद में लोनी के ट्रॉनिका सिटी में ई-स्कूटी और ई-रिक्शा बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं, मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी है।

बता दें कि आग इतनी भयंकर लगी है कि अन्य स्टेशनों से आग बुझाने के लिए गाड़ियों को बुलाया गया है। फिलहाल दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है।

इस फैक्ट्री में करीब 50 लोग काम करते थे। फैक्ट्री में कितना नुकसान हुआ है। अभी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। शॉर्ट-सर्किट से आग लगने की बात बताई जा रही है।

गाजियाबाद की आशियाना ग्रीन्स सोसायटी में खाली मैदान में भरा पानी, पनप रहे मच्छर; बीमारी फैलने की आशंका

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्थित आशियाना ग्रीन्स सोसायटी के पीछे खाली पड़े मैदान में झाड़ियां उगी हुई हैं और पानी जमा हो गया है। इसमें असामाजिक लोगों का आना-जाना लगा रहता है। सोसायटी के लोगों को डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैलने का डर है। आरडब्ल्यूए ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर समस्या का समाधान करने की मांग की है।

गाजियाबाद। इंदिरापुरम के अहिंसा खंड-2 स्थित आशियाना ग्रीन्स सोसायटी के पीछे काफी बड़ा मैदान खाली पड़ा है। इसमें झाड़ियां उगी हुई हैं, जिससे यहां नीलगाय, सांप और असामाजिक लोगों का आना-जाना लगा रहता है।

पानी से आ रही बदबू

इससे सोसायटी की सुरक्षा को लेकर लोगों में हर समय डर का माहौल रहता है। साथ ही बारिश की वजह से खाली मैदान में पानी जमा हो गया है जिसमें मच्छर पनप रहे हैं और बदबू आ रही है। इससे सोसायटी के लोगों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैलने की आशंका है।

जीडीए से की समाधान की मांग

आशियाना ग्रीन्स सोसायटी के आरडब्ल्यूए के सचिव देवेंद्र राघव ने बताया कि हमारी सोसायटी की बाउंड्रीवाल गिर गई है, जिससे खाली मैदान में पानी भर गया है और सुरक्षा को लेकर भी खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर उन्होंने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर समस्या का समाधान कराने की मांग की है।

संरक्षित हों तीर्थस्थल की हिन्दू वंशावलियों की पंजिका

अशोक मधुप

हिंदू परिवारों को इस बारे में बहुत कम या न के बराबर जानकारी है। उन्हें पता भी नही कि इन स्थानों पर उनके परिवार का इतिहास संग्रहित है। सदियों से बहियों में ये रिकार्ड व्यापारी के खाते की तरह लिखकर रखा जा रहा है।

हिंदू तीर्थस्थल धार्मिक मान्यताओं और पूजन अर्चन के लिए विख्यात है। इन सब कार्य को इन स्थलों के ब्राह्मण पंडित कराते हैं। ये ब्राह्मण पंडित पंडा कहे जाते हैं। ये पंडा सदियों से एक कार्य करते और कराते आ रहे हैं। ये पंडा अपने पास आने वाले यजमान (भक्तों) के परिवार का इतिहास अपनी बहियों में संजोते जा रहें हैं। ये काम सदियों से अनवरत रूप से जारी है। ये हिन्दू वंशावलियों की पंजिकाएं ऐतिहासिक धरोहर हैं। आज इनके संरक्षण की आवश्यक्ता है। इनके संजोकर रखने की जरूरत है।

हिंदू परिवारों को इस बारे में बहुत कम या न के बराबर जानकारी है। उन्हें पता भी नही कि इन स्थानों पर उनके परिवार का इतिहास संग्रहित है। सदियों से बहियों में ये रिकार्ड व्यापारी के खाते की तरह लिखकर रखा जा रहा है। अधिकतर भारतीयों व वे परिवार जो विदेश में बस गए उनको आज भी पता नहीं कि इन तीर्थस्थल की पंडो की बहियों में उनके परिवार की वंशावली दर्ज है। हिन्दू परिवारों की पिछली कई पीढ़ियों की विस्तृत वंशावलियां इन पंडा के पास संग्रहित हैं। ये पंडा आने वाले यजमान से उसके परिवार की जानकारी नोट करने के बाद उसके हस्ताक्षर कराकर बही में अपने पास रखते हैं। ये पंडा ये बहियां अपनी आने वाली अपनी पीढ़ी को सौंपते जाते हैं। ये बहियां जिलों व गांवों के आधार पर वर्गीकृत की गयीं हैं। प्रत्येक जिले की पंजिका का विशिष्ट पंडित होता है। यहाँ तक कि भारत के विभाजन के उपरांत जो जिले व गाँव पाकिस्तान में रह गए व हिन्दू भारत आ गए उनकी भी वंशावलियां यहाँ हैं। कई स्थितियों में उन हिन्दुओं के वंशज अब सिख हैं, तो कई के मुस्लिम अपितु ईसाई भी हैं। किसी किसी की सात वंश या उससे भी ज्यादा की जानकारी पंडों के पास रखी इन वंशावली पंजिकाओं से होना साधारण सी बात है।

शताब्दियों पूर्व से हिन्दू पूर्वजों ने हरिद्वार या किसी पावन नगरी की यात्रा की/ तीर्थयात्रा के लिए या/ शव-दाह या स्वजनों के अस्थि व राख का गंगा जल में किया होगा तो वे संबद्ध पंडा के पास गए होंगे। ये पंडा इन आने वालों के रहने खाने तक की व्यवस्था करते हैं। इन पंडाओं ने अपनी पंजिका में वंश-वृक्ष को संयुक्त परिवारों में हुए सभी विवाहों, जन्म व मृत्युओं के विवरण दर्ज किया हुआ हैं। वर्तमान में धार्मिक स्थल पर जाने वाले भारतीय हक्के-बक्के रह जाते हैं जब वहां के पंडित उनसे उनके अपने वंश-वृक्ष को नवीनीकृत कराने को कहते हैं।

आजकल जब संयुक्त हिदू परिवार का चलन ख़त्म हो गया है। लोग एकल परिवारों को तरजीह दे रहे हैं, ये पंडित चाहते हैं कि आगंतुक अपने फैले परिवारों के लोगों व अपने पुराने जिलों- गाँवों, दादा- दादी के नाम व परदादा-परदादी और विवाहों, जन्मों और मृत्यु, परिवारों में हुए विवाह आदि की पूरी जानकारी के साथ वहां आएं। आगंतुक परिवार के सदस्य को सभी जानकारी नवीनीकृत करने के उपरांत वंशावली पंजीका को भविष्य के पारिवारिक सदस्यों के लिए व प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के लिए हस्ताक्षरित करना होता है। साथ आये मित्रों व अन्य पारिवारिक सदस्यों से भी साक्षी के तौर पर हस्ताक्षर करने की विनती की जा सकती है।

इन तीर्थ स्थल के पुरोहितों के पास देश और दुनिया भर के यजमानों का दशकों पुराना लिखित रिकॉर्ड वंशावली के रूप में मौजूद है। किसी यजमान के आने पर चंद मिनटों में ही संबंधित पुरोहित कंप्यूटर से भी तेज गति से वंशावली देखकर उनके पूर्वजों की जानकारी दे देते हैं। पितृ पक्ष के दौरान इन तीर्थ स्थल पर आने वाले लोग अपने तीर्थ पुरोहितों के पास आकर वंशावली में अपने वंश के बारे में जरूर जानते हैं। ये पडे जनपद के हिसाब से हैं। तीर्थ स्थल में पहने वालों को पता है कि किस जनपद के पंडा कौन हैं। किसी दूसरे के यजमान को कोई अन्य पंडा खुद क्रियाकर्म नहीं कराता। संबधित जिले के पंडा के पास उसे भेज देता है।

शताब्दियों से हो रहा ये लेखन भोज पत्रों और ताम्र पत्रों के बाद अब कागज की बहियों पर शुरू किया गया। तीर्थ पुरोहितों के पास सैकड़ों वर्ष पुरानी बहियां आज भी सुरक्षित हैं। तीर्थ पुरोहितों की बहियों में देश भर के राजाओं, महाराजाओं, साधु, संतों, राजनेताओं एवं आम लोगों के परिवारों के वंश लेखन बहियों में मौजूद हैं। अकेले हरिद्वार में 30 हजार से अधिक की संख्या में वंशावली की बहियां सुरक्षित और संरक्षित हैं। इन बहियों में लेखन करने के लिए अलग स्याही तैयार करके तीर्थ पुरोहित वही लेखन करते हैं, जो काफी वर्षों तक सुरक्षित रहती है। इन वंशावलियों में जातियों, गोत्रों, उपगोत्रों का भी जिक्र रहता है। सबसे अहम बात इन बहियों में देखने को मिलती हैं कि तीर्थ पुरोहितों ने लेखन को भेदभाव से दूर रखा है। जहां राजाओं, महाराजाओं की वंशावलियां जिस क्रम में अंकित हैं, उसी क्रम में तीर्थ नगरी में पहुंचने वाले अन्य श्रद्धालुओं की हैं। विभिन्न राजवंशों की मुद्रांए, हस्त लेखन, दान पत्र, अंगूठे और पंजों के निशान बहियों में मौजूद हैं। यहां की वंशावलियों में देश की कई रियासतों के राजाओं के आने के उल्लेख दर्ज हैं।

अक्तूबर 2007 में हमें इंडियन वर्किंग जर्नलिस्ट की एक कांफ्रेंस में बद्रीनाथ जाने का अवसर मिला। मेरे साथ गए मेरे दोस्त नरेंद्र मारवाड़ी भी थे। हम मारवाड़ी के साथ बद्रीनाथ में, अजमेर के महावर वालों की धर्मशाला में चले गए। ये मारवाड़ी के परिवारवालों की धर्मशाला हैं। वहां पंडित जी से बात की। वंशानुक्रम के बारे में बताया। बात करते-करते पंडित जी ने अपनी बही खोलकर उनके गोत्र का विवरण खोला तो पता चला कि मारवाड़ी के पिता जी 41 वर्ष पूर्व यहां यात्रा को आए थे। यात्रा को आने के बाद हुए उनके दो बच्चों का विवरण दर्ज नहीं थे। पंडित जी ने बही देखकर बताया कि 93 साल पूर्व उनके दादा जी बद्रीनाथ आए थे। दोनों के आने की तिथि तक वही में दर्ज थी। उनके हस्ताक्षर भी बही में मौजूद थे। मित्र को अपने बाबा का नाम ज्ञात था। यहां बही से उन्होंने अपने बाबा के पिता उनके भाई, बाबा के दादा और उनके भाइयों आदि का विवरण नोट किया। पंडित जी ने अपनी वही में मित्र से अपने और उनके बच्चे, भाई और भाइयों के बच्चों की जानकारी नोट की। नीचे तारीख, माह, सन डालकर हस्ताक्षर कराए।

सदियों से चले आ रहा इतिहास को संजोकर रखना एक दुरूह कार्य है। इस कार्य को ये पंडे सुगमता से पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं। आज इस इतिहास को संजोने और संरक्षण की जरूरत है। अच्छा रहे कि इनका कंप्यूटरीकरण हो जाए। बहियों को लैमिनेट करके भी संरक्षित किया जा सकता है। कैसे भी हो, ये होना चाहिए, नहीं तो समय के साथ ये गलता और खराब होता चला जाएगा।। ये काम इनके व्यक्तिगत स्तर से संभव नहीं। सरकार को अपने स्तर से कराना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा।

- :सौजन्य :-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

कुमाऊं में स्थापित होंगे 41 ईवी चार्जिंग स्टेशन

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले समय में बाहरी राज्यों से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए इस पहल को प्राथमिकता दी जा रही है।

उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण के तहत राज्य में चारधाम यात्रा मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गंगोत्री धाम के रास्ते में केंद्र सरकार की ओर से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इस पहल से यात्रियों को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में कोई परेशानी नहीं होगी।

इसके अलावा परिवहन विभाग अब कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तैयार कर रहा है। इस योजना के तहत कुमाऊं के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर हर 35 किलोमीटर की दूरी पर कुल 41 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन चालक किसी भी आपात स्थिति में आसानी से अपने वाहनों को चार्ज कर सकेंगे और बिना किसी परेशानी के यात्रा पूरी कर सकेंगे।

संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने अपने बयान में कहा कि हमारी योजना के तहत कुमाऊं क्षेत्र के पर्यटन स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। हर 35 किलोमीटर पर कुल 41 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ताकि ई-वाहन चालक बिना किसी रुकावट के अपने वाहन चार्ज कर सकें। पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस कदम से न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को भी नई दिशा मिलेगी, जहां पर्यावरण अनुकूल साधनों के उपयोग को अधिक प्राथमिकता मिलेगी।

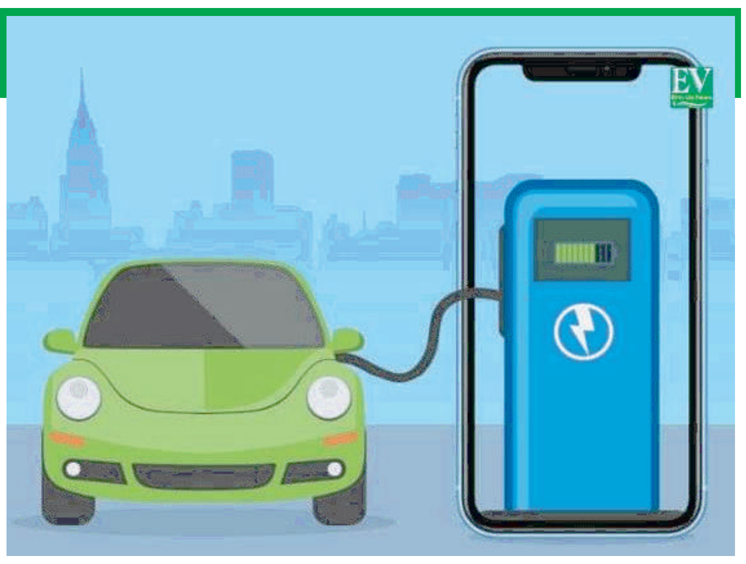

टेस्ला की भारत में प्रवेश को लेकर कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने दिया खास जवाब

परिवहन विशेष न्यूज

एलन मस्क की कंपनी टेस्ला लंबे समय से भारत में एंट्री का इंतजार कर रही है। भारत सरकार की नीतियां इस बात पर केंद्रित हैं कि घरेलू ईवी कंपनियों को नुकसान न हो। अब कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर बड़े संकेत दिए हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ी बात कही है। सीएनबीसी टीवी18 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इसका फायदा उठाने के लिए घरेलू के साथ-साथ विदेशी कंपनियां भी यहां आकर कारोबार करना चाहती हैं। भारत की ईवी निर्माता कंपनियों में टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने न सिर्फ यहां निर्माण किया है, बल्कि देश में ईवी के प्रति अच्छा रुझान बनाने में भी मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए काफी संभावनाएं लेकर आ सकता है।

टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियां जो ईवी निर्माता हैं, उनके द्वारा मेक इन इंडिया के तहत ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो ईवी को अच्छी गति दे सकते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी पहलों के लिए काफी उत्साह दिखाया है और ऐसी नीति बनाने पर काम किया है जिससे आम उपभोक्ता को फायदा हो सके। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पीएम मोदी के विजन और सोच के अनुरूप भारत में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है।

टेस्ला के बारे में पीयूष गोयल ने कहा कि कई अन्य विदेशी कंपनियां और ईवी निर्माता भारत आकर व्यापार करना चाहती हैं। भारत सरकार उन्हें यहां आकर ईवी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि देश में ईवी वाहनों की संख्या बढ़ सके। टेस्ला को भी ऐसे ही अवसर मिलेंगे जिसके जरिए वह भारत में व्यापार कर सकती है और यहां के विशाल बाजार का आनंद ले सकती है।

पीयूष गोयल ने कहा कि हम नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आए हैं, ताकि ईवी कंपनियां भारत में आकर आसानी से कारोबार कर सकें। उन्होंने इसके बारे में बताया -

01. पहले उपाय के तहत ईवी निर्माता कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी और इसके तहत ऐसी कंपनियां भारत में आकर यहां निर्माण कर सकती हैं और ईवी वाहनों पर सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं।

02. दूसरे उपाय के तहत इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों को ईवी वाहन आयात करने का विकल्प दिया जा रहा है ताकि वे कम आयात शुल्क पर भारत में इलेक्ट्रिक वाहन आयात कर सकें। इसका फायदा यह होगा कि इससे देश में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी और सस्ते आयातित ईवी वाहनों की संख्या बढ़ेगी।

टाटा नेक्सन का इलेक्ट्रिक अवतार अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दे रहा है सबको मात

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा नेक्सन ईवी भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। यह कार अपनी बेहतरीन रेंज, दमदार परफॉर्मेंस, आकर्षक डिज़ाइन और किफ़ायती कीमत की वजह से लोकप्रिय है। नेक्सन ईवी ने भारत में इलेक्ट्रिक कार बाज़ार में एक नया मानक स्थापित किया है।

टाटा नेक्सन ईवी में एक शक्तिशाली बैटरी पैक है जो एक बार चार्ज करने पर 312 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है। कार 130 बीएचपी की अधिकतम शक्ति और 245 एनएम का पीक टॉर्क उत्पन्न करती है, जिससे इसे तेज़ गति मिलती है। नेक्सन ईवी में इको और स्पोर्ट दो ड्राइविंग मोड हैं, जो अलग-अलग ड्राइविंग स्थितियों के लिए अनुकूलित हैं।

टाटा नेक्सन ईवी का डिज़ाइन आधुनिक और स्टाइलिश है। इसमें एलईडी हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स, रूफ रेल्स और एलईडी टेललाइट्स जैसे कई आकर्षक तत्व हैं। कार का इंटीरियर आरामदायक और प्रीमियम फील देता है, जिसमें अल्केन्टारा सीट अपहोल्स्ट्री, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई अन्य फीचर्स हैं।

टाटा नेक्सन ईवी की कीमत भारत में काफी किफायती है, जिससे यह कई भारतीय खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गई है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक कारों के रखरखाव की लागत बहुत कम होती है, क्योंकि उन्हें इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग या अन्य पारंपरिक कारों की तरह नियमित सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं होती है।

टाटा नेक्सन ईवी की सफलता ने भारत में इलेक्ट्रिक कारों के भविष्य के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है। सरकार भी इलेक्ट्रिक कारों को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियां और सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह उम्मीद की जाती है कि आने वाले वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या में काफी वृद्धि होगी।

जियो-बीपी ने लॉन्च किया 500वां ईवी-चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट्स हुए 5 हजार

परिवहन विशेष न्यूज

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के निदेशक अनंत मुकेश अंबानी और बीपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मुरे ऑचिंकलोस ने जियो-बीपी के 500वें जियो-बीपी पल्स ईवी-चार्जिंग स्टेशन का बृहस्पतिवार, 26 सितंबर को उद्घाटन किया। जियो-बीपी, आरआईएल और वैश्विक ऊर्जा कंपनी बीपी के बीच ईंधन तथा परिवहन का संयुक्त उद्यम है। इस चार्जिंग स्टेशन के ओपन होने के बाद मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र, जियो वर्ल्ड प्लाजा और जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पहुंचने वाले लोग आसानी से अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर पाएंगे।

लॉन्च के मौके पर अनंत अंबानी ने कहा कि "भारत में ईवी अपनाने में तेजी लाने में जियो-बीपी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। फास्ट-चार्जिंग स्टेशनों के सबसे बड़े नेटवर्क शेयर, ईवी-चार्जिंग इंफ्रा में सबसे तेज वृद्धि और उच्चतम विश्वसनीयता के साथ, जियो-बीपी लाखों भारतीयों को डिजिटल चार्जिंग सॉल्युशन दे रहा है"।

जियो-बीपी ने ईवी-चार्जिंग पॉइंट्स की तादाद मात्र एक साल में 1,300 से बढ़कर 5,000 हो गई है। इनमें से 95 फीसदी ईवी-चार्जिंग पॉइंट्स फास्ट-चार्जिंग कर सकते हैं। जियो-बीपी पहली कंपनी है जिसने टॉप-रेटेड 480 किलोवाट चार्जर लगाए हैं। मॉल, सार्वजनिक पार्किंग, कॉर्पोरेट पार्क, होटल और वेसाइड सुविधाओं जैसे स्थानों पर ये चार्जिंग पॉइंट्स त्वरित चार्जिंग कर रहे हैं। एक तरह से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाकर जियो-बीपी इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दे रही है।

देश का छोटा सा राज्य इलेक्ट्रिक बसें चलाने में सबसे आगे

परिवहन विशेष न्यूज

ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी दो पहिया से लेकर चार पहिया वाहनों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकारें भी सीएनजी बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाने को प्राथमिकता दे रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिक बसों के मामले में बड़े राज्य पीछे हैं, जबकि छोटे राज्य आगे हैं।

सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक छोटे राज्यों के मामले में देश की राजधानी दिल्ली सबसे आगे है। यहां फिलहाल 2011 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। देश में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। यहां 2111 बसें चल रही हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र के मुकाबले दिल्ली काफी छोटी है और अंतर सिर्फ 100 बसों का है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 1195 बसें चल रही हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, जहां 758 बसें चल रही हैं और गुजरात पांचवें नंबर पर है, जहां 894 बसें चल रही हैं।

पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर और मिजोरम में सिर्फ 1-1 बस चल रही है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 4, झारखंड में 7 और राजस्थान में सिर्फ 24 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में सिर्फ 181 बसें चल रही हैं। मंत्रालय लगातार राज्यों से सार्वजनिक परिवहन के तौर पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने का आग्रह कर रहा है, इस संबंध में पत्र भी लिखे गए हैं।

मंत्रालय सुविधाजनक यात्रा के लिए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर 38, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 51, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 10, ट्रांस राजस्थान एक्सप्रेसवे पर 4, इंदौर-हैदराबाद पर 6, रायपुर विशाखापत्तनम पर 12 ईवी चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही मार्च 2025 से पहले 200 और ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना हुआ और भी सस्ता! रोड टैक्स पर मिलेगी बड़ी छूट

परिवहन विशेष न्यूज

कर्नाटक सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस घटाने का प्रस्ताव दिया है, ताकि इको-फ्रेंडली वाहनों की बिक्री में तेजी आ सके। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देने की भी योजना बनाई गई है, ताकि राज्य को स्वच्छ मोबिलिटी के क्षेत्र में और आगे ले जाया जा सके।

कर्नाटक सरकार की इस नई नीति के तहत 25 लाख रुपये से कम कीमत वाली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स को मौजूदा 18 फीसदी से घटाकर 13 फीसदी करने का प्रस्ताव है। यह छूट केवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर लागू होगी, माइल्ड हाइब्रिड मॉडल पर नहीं। यह नीति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में घोषित नीति के समान है, जहां लोगों को इको-फ्रेंडली वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हाइब्रिड कारों पर टैक्स में छूट दी गई थी।

सरकार ने न केवल हाइब्रिड कारों बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं को भी कई लाभ प्रदान करने की योजना बनाई है। प्रस्ताव के अनुसार राज्य में नई फैक्ट्रियां लगाने या मौजूदा फैक्ट्रियों का विस्तार करने वाली कंपनियों को उनकी जमीन और मशीनरी पर 15 से 25 प्रतिशत तक का बढ़ावा दिया जा सकता हैं।

यह बढ़ावा बैटरी कंपोनेंट और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनियों पर भी लागू होगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को भी उनके निवेश के आधार पर 25 प्रतिशत तक का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ कंपनी को दिए जाने वाले निवेश और रोजगार के अवसरों के हिसाब से तय किया जाएगा।

कर्नाटक सरकार का यह कदम स्वच्छ और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग पर्यावरण के अनुकूल वाहन अपनाएं, जिससे प्रदूषण कम हो। सरकार का यह प्रस्ताव केवल इलेक्ट्रिक वाहनों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें हाइब्रिड और हाइड्रोजन जैसे अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले वाहन भी शामिल होंगे।

इस नीति को अंतिम रूप देने के लिए कोई निश्चित समय अवधि तय नहीं की गई है, लेकिन इसे जल्द ही लागू करने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य

विजय गर्ग

कई शिक्षित भारतीयों ने, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, क्षेत्रीय भाषाओं को दरकिनार करते हुए अंग्रेजी को अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में अपनाना शुरू कर दिया। इसने अंग्रेजी-शिक्षित अभिजात वर्ग और मूल भाषा बोलने वाले लोगों के बीच एक भाषाई विभाजन पैदा किया। ऐतिहासिक एनईपी 2020 में शिक्षा प्रणाली में क्षेत्रीय भाषाओं पर हमारा ध्यान फिर से केंद्रित करने की कल्पना की गई है।

उच्चतर प्रदान करने के खतरे स्थानीय भाषाओं में शिक्षा उच्च शिक्षा में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ाना है, लेकिन यह शिक्षा की गुणवत्ता के लिए चुनौतियाँ भी पैदा कर सकता है शिक्षा अंग्रेजी में दी जानी चाहिए या किसी क्षेत्रीय भाषा में, यह बहस हमारे स्वतंत्रता के बाद के समाज में सक्रिय रूप से चलती रही है। यह सच है कि एक राष्ट्र के रूप में हमें अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करना होगा, लेकिन साथ ही, हमें अपनी वर्तमान पीढ़ी को भविष्य में अंतरिक्ष युग और एआई जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। उपनिवेशीकरण के दौरान विदेशियों का काम आसान करने के लिए अंग्रेजी हम पर थोपी गई। उस प्रक्रिया में हमारी भूमि पर शासन करने वाले विदेशी शासकों ने हमारे समृद्ध वैज्ञानिक ज्ञान को समझने के लिए देशी भाषाएँ भी सीखीं, कभी-कभी देशी भारतीयों से भी बेहतर। इस वजह से, वे मूल भारतीयों की तुलना में भारतीय ज्ञान प्रणालियों के बारे में बेहतर विद्वतापूर्ण कार्य करने में सक्षम थे। इससे लंबे समय में दुनिया को भारतीय ज्ञान को पहचानने में मदद मिली है। दूसरी ओर, अंग्रेजी के प्रभुत्व ने कई देशी भाषाओं की स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया है। ब्रिटिश शैक्षिक सुधारों ने विशेषकर उच्च स्तरों पर अंग्रेजी-माध्यम शिक्षा को प्राथमिकता दी। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां अंग्रेजी में दक्षता सत्ता, नौकरियों और सामाजिक गतिशीलता तक पहुंच का पर्याय बन गई। कई शिक्षित भारतीयों ने, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, क्षेत्रीय भाषाओं को दरकिनार करते हुए अंग्रेजी को अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में अपनाना शुरू कर दिया। इसने अंग्रेजी-शिक्षित अभिजात वर्ग और मूल भाषा बोलने वाले लोगों के बीच एक भाषाई विभाजन पैदा किया। ऐतिहासिक एनईपी 2020 में शिक्षा प्रणाली में क्षेत्रीय भाषाओं पर हमारा ध्यान फिर से केंद्रित करने की कल्पना की गई है। दुर्भाग्य से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने पर इसका ध्यान अत्यधिक सक्रियता के कारण समस्याग्रस्त हो गया है। कई राज्य विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा पाठ्यपुस्तकों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने में शामिल हैं। हालाँकि ये हमारी भाषाओं को संरक्षित करने के लिए एक मूल्यवान दस्तावेज़ के रूप में काम करेंगे, लेकिन ये उच्च शिक्षा की

गुणवत्ता में सुधार करने में मदद नहीं करेंगे। एनईपी से पहले भी कई राज्य विश्वविद्यालयों में विज्ञान को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने का प्रावधान था। लेकिन उसके लिए बहुत कम खरीदार थे। आज भी जब हम क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार करते हैं तो उसका क्रियान्वयन एकसमान रूप से नहीं हो पाता है। ये सभी नीतिगत बदलाव, अच्छे या बुरे, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रभावित करेंगे। दुर्भाग्य से, हमारे सरकारी कर्मचारियों, राजनेताओं या यहां तक कि कार्यकर्ताओं के किसी भी बच्चे इन सार्वजनिक क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि इससे गुणवत्ता में सुधार होगा या नहीं। तो यह सारा भाषा प्रेम 'केवल दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं'। यह संस्कृति फिर से हमारे समाज में भाषाई विभाजन पैदा कर रही है, जो अंग्रेजों ने बहुत पहले हमारे साथ किया था। हम इसे पसंद करें या नहीं, अंग्रेजी ही एकमात्र भाषा है जो हमारे देश के विभिन्न वर्गों को जोड़ने वाले पुल के रूप में कार्य करती है। और उच्च शिक्षा में, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में जहां जानकारी अन्य देशों में उत्पन्न ज्ञान से एकत्र की जाती है, यह एकमात्र ऐसी भाषा बन गई है जो हमें वैश्विक ज्ञान केंद्र से जोड़ सकती है। यदि वे अंग्रेजी समझने में सक्षम नहीं हैं तो हम अच्छे इंजीनियर या वैज्ञानिक कैसे तैयार कर सकते हैं? यदि क्षेत्रीय भाषा में इंजीनियरिंग या विज्ञान पाठ्यक्रम की पेशकश की जाती है तो क्या कोई खरीदार होगा? हमारे भविष्य के युवा कैसे जीवित रहेंगे? एक एआई प्रभुत्व वाली डिजिटल दुनिया जहां वैश्विक कार्यबल के लिए अंग्रेजी भाषा है? वे अंतरिक्ष कॉलोनी में कैसे जीवित रहेंगे? अंग्रेजी निस्संदेह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की वैश्विक भाषा है। अधिकांश अत्याधुनिक वैज्ञानिक पेपर, इंजीनियरिंग मैनुअल और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट अंग्रेजी में प्रकाशित होते हैं। हालाँकि जटिल वैज्ञानिक तथ्यों को पढ़ाने के लिए शिक्षा की द्विभाषी पद्धति को अपनाया जा सकता है, लेकिन हमारी उच्च शिक्षा से अंग्रेजी की पूरी तरह से उपेक्षा हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए मौत का जाल होगी। अनावश्यक भाषाई अंधराष्ट्रवाद उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को नष्ट कर देगा।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट - 152107 पंजाब

आवास की तलाश में हिंसक होते जीव : विजय गर्ग

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले बहराइच में पिछले दिनों भेड़ियों का भीषण आतंक फैला था। वहां बीते मार्च में शुरू हुए भेड़ियों के हमलों में अब तक सर्वाधिक शिकार इलाके के छोटे-छोटे बच्चे हुए हैं। इन हमलों में अब तक नौ बच्चों समेत लगभग दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चालीस से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में भी अधिकांश बच्चे ही हैं। यों भेड़िए ही नहीं, हाथी, शेर, सियार, तेंदुआ, चीता, भालू और बाघ जैसे बेहद खूंखार और भयावह वन्य पशुओं की मानव बस्तियों में घुसपैठ और उनके द्वारा मनुष्यों, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर हमले की घटनाएं दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र में बाघों, भालुओं, तेंदुओं और जंगली हाथियों, मध्यप्रदेश में सियारों और पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगली हाथियों के हमले जैसे आए दिन की बात हैं। निर्विवाद रूप से ये घटनाएं अत्यंत दुखद और भयावह हैं। इसलिए लोगों का आक्रोशित होना उचित है, लेकिन प्रश्न है कि आखिर जंगल में आजाद विचरने, छोटे वन्य पशुओं का शिकार कर अपना तथा परिवार का भरण-पोषण करने और सामान्यतया अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने वाले ये भेड़िए इतने खूंखार क्यों हो गए कि छोटे-छोटे मासूम बच्चों को मारकर खाने लगे।

दरअसल, देश भर में जंगलों की बेतरतीब कटाई के कारण वन्य पशुओं का आशियाना दिनोंदिन उजड़ता जा रहा है। आज विश्व की कुल जनसंख्या आठ अरब से अधिक हो चुकी है और प्रति वर्ष इससे दो गुने से ज्यादा, लगभग अठारह अरब वृक्षों की कटाई हो रही है। पेड़ों की इस अंधाधुंध कटाई की भरपाई का एक ही तरीका हो सकता है और वह है तीव्र गति से नए पौधों का रोपण और उनकी देखभाल करना। यानी जितने पेड़ प्रति वर्ष काटे जा रहे हैं, कम से कम उतने पौधे भी दुनिया भर में लगाए जाएं। हालांकि उन पौधों के पेड़ बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए वास्तव में पौधरोपण की जो वर्तमान दर और गति है, उससे लगातार नष्ट किए जा रहे जंगलों के एवज में नए जंगल उगा पाना संभव नहीं है। पौधरोपण वन्य पशुओं के प्राकृतिक रहवास और पर्यावरण दोनों को बचाने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, किंतु इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए पौधरोपण की गति को इस हद तक बढ़ाना होगा कि जितने वृक्ष प्रति वर्ष दुनिया भर में काटे जाते हैं, कम से कम उससे डेढ़ गुना पौधे लगाए जाएं। फिलहाल प्रति वर्ष अठारह अरब काटे जाने वाले वृक्षों की तुलना में दुनिया भर में मात्र पांच अरब पौधे लगाए जा रहे हैं। जाहिर है में कि इस प्रकार पेड़ों की अंधाधुंध

कटाई की भरपाई संभव नहीं होगी।

भारत में भी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई जारी है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 21 मार्च, 2022 को बताया था कि वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और विकास के लिए लगभग 31 लाख पेड़ काट दिए गए। वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत काटे गए पेड़ों के बदले में प्रतिपूरक वनीकरण की योजना चलाकर केंद्र सरकार ने 359 करोड़ रुपए की लागत से 3.6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए, जो नाकाफी लगते हैं, क्योंकि फिलहाल इससे संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि उनमें से कितने पौधे बचाए गए और कितने नष्ट होने के लिए छोड़ दिए गए। बहरहाल, वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण दिनोंदिन वन्य पशुओं का प्राकृतिक रहवास सिकुड़ता जा रहा है, इससे इनके लिए भोजन- पानी की समस्या पैदा हो गई है। इसीलिए वन्य पशु भोजन-पानी की तलाश में मानव बस्तियों की ओर पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। वैसे, भेड़िए स्वभाव से खूंखार तो होते हैं, पर सारे भेड़िए आदमखोर नहीं होते। हालांकि प्रतिशोध लेने में ये बड़े माहिर होते हैं इसलिए अगर इनको या इनके परिवार के सदस्यों को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाए, तो ये कतई सहन नहीं करते और अपने शत्रुओं से बदला लेते हैं।

आज से लगभग पच्चीस वर्ष पहले ऐसी ही एक घटना सुर्खियों में आई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलों में सई नदी के कछार पर भेड़ियों के हमलों में इलाके के पचास से भी अधिक मासूम बच्चों की मौत हो गई थी उसकी पड़ताल करने पर पता चला था कि इंसान के कुछ बच्चों ने भेड़ियों की एक मांद में घुसकर उनके दो बच्चों को मार डाला था, जिसके प्रतिशोध में भेड़ियों ने हमले कर मनुष्यों के पचास से अधिक मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। उस दौरान वन विभाग द्वारा चलाए गए भेड़ियों के धर-पकड़ अभियान में कुछ भेड़िए पकड़े भी गए थे, लेकिन उनके बीच में मौजूद आदमखोर जोड़ा हमेशा बचता रहा और बदला लेने के कोशिश में लगातार कामयाब भी होता गया। हालांकि बाद में आदमखोर भेड़ियों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा गोली मार दी गई और अंततः भेड़ियों का खूनी आतंक खत्म हो पाया था। गौर करें तो बहराइच की घटनाओं में भी भेड़ियों का वही व्यवहार नजर आता है। इसलिए इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि भेड़िए अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने या उनकी हत्या करने का बदला ले रहे हों। बहरहाल, दुख की बात यह है कि एक बार फिर भेड़ियों की जान खतरे में आ गई है, क्योंकि शासन-प्रशासन की ओर से इन्हें गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। वैसे भेड़ियों के विरुद्ध की जाने वाली सरकारी कार्रवाइयों पर गौर करें तो उनके जीवन का सर्वाधिक स्याह पक्ष अंग्रेजों के समय का है, जब ब्रिटिश सरकार की ओर से भेड़ियों को मारने का बड़ा अभियान चलाकर चालीस वर्षों में एक लाख से अधिक भेड़ियों को शिकारियों ने मार डाला था और ब्रिटिश राज की तरफ से ईनाम भी प्राप्त किया था।

देखा जाए तो मनुष्य और वन्य पशुओं के बीच जारी संघर्षो का यह सिलसिला बेहद गंभीर और चिंताजनक है। इसलिए समय रहते इसका हल ढूंढ़ना जरूरी है अन्यथा यह समस्या अत्यंत विकराल रूप ले सकती है। जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारें वन्य प्राणी विशेषज्ञों की सलाह लेकर वन्य पशुओं के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने तथा बड़े स्तर पर वनीकरण अभियान चलाकर वनों के विकास करने की दिशा में कुछ ठोस और सकारात्मक कदम उठाएं, ताकि हमारे वन्य जीव आजादी से अपने घरों में बेफिक्र होकर रह सकें। संभव है कि इन प्रयासों के फलीभूत होने में कई वर्ष लग जाएं, लेकिन इस दौरान एक कार्य किया जा सकता है, वह है इन वन्य प्राणियों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर इन वन्य पशुओं के विरुद्ध क्रूरता के बदले में दया का भाव दर्शाया जाए और इनको लाड़-प्यार दिया जाए, तो मनुष्यों के प्रति इनके हिंसक व्यवहार में भी परिवर्तन आ सकता है।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट - 152107

राय

जेनरेटिव एआई में कर लें अपनी तैयारी

विजय गर्ग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जेनरेटिव एआई का इन दिनों बोलबाला है। लगभग सभी उद्योग एआई का उपयोग अपने डिजिटल मंच पर कर रहे हैं। इसी के चलते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मानें, तो एक ओर पहले से चली आ रही कुछ तरह की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, तो वहीं 13.3 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियों के मौके बनेंगे। जिसमें से कई एक में एआई और मशीन लर्निंग के स्किल की जरूरत होगी। इसी रिपोर्ट के अनुसार एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में आने वाले साल तक 9.7 करोड़ नई नौकरियां बनेंगी। यानी टेक्नोलॉजी के पेशेवरों और ग्रेजुएट्स के लिए इस क्षेत्र में तैयारी करने का सही समय है, ताकि वे भविष्य में इन मौकों का लाभ उठा सकें। इस महत्वपूर्ण तकनीक से संबंधित स्किल की तैयारी में सही आदर्शों को भी ध्यान में रखना होगा।

क्या है जेनरेटिव एआई

जेनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है, जो नया कंटेंट बनाने में मददगार बन रही है। इस तरह यह कई एक उद्योगों में बड़े बदलाव लाने में समर्थ हो रही है। जेनरेटिव एआई के माध्यम से सोशल मीडिया के लिए लेख लिखने, इमेजेस बनाना, नए संगीत की रचना करने और उत्पादों को डिजाइन करने और यहां तक कि कोडिंग जैसे काम भी लिए जा सकते हैं।

मौके और पद

यह तेजी से विकास करता तकनीकी क्षेत्र है, जो टेक्नोलॉजी संबंधित उद्योगों, हेल्थकेयर, मनोरंजन और फाइनेंस के क्षेत्र में देश और विदेश में काम के मौके बना रहा है। इस क्षेत्र में एआई रिसर्च साइंटिस्ट्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर और क्रिएटिव एआई डेवलपरों की बहुत मांग है। कैसे तैयारी करें

गैर तकनीकी क्षेत्र के लोगों के लिए अगर आप गैर तकनीकी क्षेत्र से हैं, तो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्टरी कोर्स करें यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से संबंधित आधारभूत जानकारी से आपको लैस करेगा। कोर्सेरा, एडएक्स और खान एकेडेमी में काफी ऐसे कोर्स मिल जाएंगे, जो आप आसानी से कर सकेंगे।

तकनीकी क्षेत्र के लोगों के लिए: अगर आपके पास तकनीकी डिग्री है या टेक दुनिया के पेशेवर हैं, तो मशीन लर्निंग, नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और अन्य प्रमुख एआई संबंधित सिद्धांतों पर पकड़ बनानी होगी। मशीन लर्निंग और एआई के लिए पायथन आदर्श लेंग्वेज है। टैसरफ्लो, पाईटॉर्च और केरास जैसी लाइब्रेरी की जानकारी लें ये टूल्स मॉडल के विकास करने और उस पर प्रयोग करने में सहायक होते हैं। कोडिंग का अभ्यास करें। न्यूरल नेटवर्क, बैकप्रपोगेशन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, वेरिएशनल ऑटोएनकोडर्स (बीएई), जेनरेटिव एडवरसरियल नेटवर्क्स (जीएएन) और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल करें। अगर आपको एआई की अच्छी समझ है और रुचि भी है, तो एआई में मास्टर्स कोर्स या एडवांस कोर्स करने की जरूर सोचें। इस क्षेत्र में शोध कार्यों के मौकों को लेकर आपकी योग्यता बढ़ेगी।

रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर ध्यान दें : जेनरेटिव एआई सिर्फ कोडिंग नहीं है। यह समझें कि कैसे आर्ट और लेखन जैसे क्षेत्रों में यह उपयोग की जा रही है। साथ ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइंस, मार्केटिंग और बहुत से क्षेत्रों में भी इस क्षेत्र में एक समग्र नजरिया आपको आगे रखेगा।

व्यावहारिक अनुभव लें एआई मॉडल को बनाने और प्रशिक्षित करने का व्यावहारिक परिस्थितियों में अभ्यास बहुत जरूरी है। जेनरेटिव एआई से इमेज क्रिएशन, राइटिंग और अनुवाद आदि की प्रतियोगिताओं, जैसे कोडिंग बूटकैंप, हैकेथॉन आदि में हिस्सा लें अलग-अलग मॉडल्स के आर्किटेक्चर पर काम करें, ताकि उनके काम करने की प्रक्रिया की समझ बढ़े। ऐसे लोगों से ऑनलाइन और ऑफलाइन संपर्क बनाएं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फोरम से जुड़ें। ऑफलाइन सेमिनार या वर्कशॉप करें।

अपना हुनर दिखाएं भी इस तकनीक में अपनी योग्यता जाहिर करने के लिए सुरक्षित और उपयोगी जेनरेटिव एआई एप्लीकेशन के कुछ प्रोजेक्ट बनाएं। इसके लिए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स की टीम का हिस्सा बनें अपनी जानकारी जाहिर करते उपयोगी ब्लॉग्स लिखें। ऐसे मेंटर ढूंढें, जो जेनरेटिव एआई को रचनात्मक क्षेत्रों से जोड़ते हुए बढ़िया काम करने के लिए जाने जाते हो। उनका मार्गदर्शन आपके लिए मददगार साबित होगा। # क्षेत्र विशेष के लिए एआई के स्किल सीखें: एआई के उपयोग से कंपनियां अपने उत्पादों और कामकाज को बेहतर बनाती हैं। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत होगी, जो इस तकनीक से मदद कर सकें। ऐसे में आपको क्षेत्र विशेष की गहरी जानकारी होना भी जरूरी है। जैसे हेल्थकेयर, शिक्षा, टूर एंड ट्रैवेल का क्षेत्र। इससे आपको रोजगार पाने की क्षमता और महत्व बढ़ेगा। जेनरेटिव एआई में आपको जगह बनाने के लिए मेहनत तो लगेगी, लेकिन भविष्य आपका होगा।

पांच कानून जिनके बारे में हर भारतीय महिला को पता होना चाहिए

विजय गर्ग

भारत का विशाल सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य समानता और न्याय के लिए प्रयासरत महिलाओं के लिए अपनी चुनौतियों के साथ आता है। इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, महिलाओं को उनके लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। इन कानूनों को समझने से न केवल महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलती है बल्कि उन्हें अपनी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने का अधिकार भी मिलता है। एडवोकेट डॉ. रेनी जॉय ने टीओआई के साथ पांच महत्वपूर्ण कानून साझा किए हैं, जिन्हें हर भारतीय महिला को सुरक्षित रहने के लिए जानना चाहिए।

समान काम के लिए समान वेतन

भारतीय कानून के तहत प्रमुख सुरक्षाओं में से एक समान वेतन का अधिकार है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 (ईआरए) के अनुसार, समान कार्य या समान कार्य करने वाले पुरुषों और महिलाओं को समान भुगतान किया जाना चाहिए। यह कानून नियुक्ति और पदोन्नति में लैंगिक भेदभाव को भी रोकता है। समान वेतन की गारंटी देकर, ईआरए महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने में मदद करता है और कार्यस्थल में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, खासकर उन उद्योगों में जहां आमतौर पर पुरुषों का वर्चस्व होता है

कार्यस्थल उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, या पीओएसएच अधिनियम, कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत कंपनियों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए सिस्टम स्थापित करने और आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) स्थापित करने की आवश्यकता है। महिलाओं को उत्पीड़न की रिपोर्ट करने का अधिकार है, जो एक सुरक्षित और अधिक सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाने में मदद करता है।

घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005) एक महत्वपूर्ण कानून है जो शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, यौन और आर्थिक हिंसा सहित घर पर दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह कानून महिलाओं को दुर्व्यवहार करने वाले परिवार के सदस्यों के खिलाफ कानूनी उपचार और सुरक्षा आदेश लेने की अनुमति देता है। यह अपराधियों के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि महिलाओं को उनके अपने घरों में नुकसान से बचाया जाए।

निःशुल्क कानूनी सहायता तक पहुंच

कठिन समय के दौरान, जैसे कि यौन उत्पीड़न या घरेलू हिंसा का सामना करना, महिलाओं को अक्सर वित्तीय और भावनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं, विशेष रूप से बलात्कार पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले। यह अधिकार गारंटी देता है कि महिलाएं अपनी वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर किसी को न्याय पाने का उचित अवसर मिले।

सक्रियता बनाम ठहराव

विजय गर्ग

जीवन सतत गतिमान बने रहने का नाम है। जब तक जीवन है, हमें सक्रिय रहना है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी भी है कि हम खुद को क्रियाशील बनाए रखें। लगातार लोगों से मिलते रहना, बोलते और सुनते रहना, सोचते रहना, अपने काम में मसरूफ रहना, एक तरह की अनवरत यात्रा में बने रहना, यकीनन खुशियां देता है, अवसाद से दूर रखता है। पर, जब भीतर से मन ठहराव चाह रहा हो, तब क्या कुछ देर के लिए किनारे जाकर खुद को मुक्त कर देना सक्रियता की तरह ही आवश्यक और स्वाभाविक नहीं होना चाहिए ?

ऐसा भी नहीं कि हमें लगातार चलते ही जाना है। लंबी यात्रा के लिए कुछ पड़ाव भी जरूरी होंगे। जीवन मे गति जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है थोड़ा-सा ठहराव। कुछ भी न करने का भाव, किसी को कुछ भी जताने, दिखाने, अपने आप को सिद्ध करने, उम्मीदों पर खरे उतरने, खुद को बदलने या लगातार बेहतर करते रहने की सनक में तब्दील होती तीव्र इच्छा जैसे अनावश्यक बोझ से खुद को कुछ समय के लिए मुक्त करने का भाव। यही जीवन का मानसिक ठहराव और तनिक विश्राम का जरूरी पड़ाव है, जो हमारी आगे की यात्रा को अर्थपूर्ण और सहज बनाता है।

कुछ भी न करने का मन, स्वस्थ और सक्रिय व्यक्ति के मन में भी आ सकता है। असल में यह मानसिक परेशानी नहीं है। यह अपने मन को आराम देने का तरीका हो सकता है, जिससे मानसिक दबाव, अवसाद से भी बचाव संभव है। यह जरूर है कि अगर ऐसा लगातार बना हुआ है, शारीरिक, मानसिक परेशानियां भी हम महसूस कर रहे हैं तो हमें चिकित्सक या अपनों से सलाह लेनी चाहिए। अपनी तात्कालिक परिस्थिति को पूरी तरह स्वीकार करते हुए हर हाल में संतुष्ट बने रहने का भाव या ठहराव, यात्रा की गति में अवरोधक नहीं बनता है। यह अल्प विराम बहुत जरूरी है, ताकि हम सही दिशा में सही तरीके से गतिवान बने रह सकें। जिस तरह सतत सक्रिय बने रहना ही हमारे अस्तित्व या जीवन का प्रमाण नहीं है, वैसे ही विश्राम या ठहराव की स्थिति भी किसी अंत की घोषणा नहीं होती। कभी- कभी ठहराव के बाद ही सही और सार्थक शुरुआत होती है। नया रास्ता दिखाई देने लगता है जो लक्ष्य के करीब पहुंचना सुगम कर देता है। स्वस्थ, नवोन्मेषी विचारों का प्रादुर्भाव भी समुचित ठहराव के बाद और शांत मनःस्थिति में संभव हो पाता। मुश्किल यह है कि जीवन की तमाम आपाधापी में इस आवश्यक विश्राम या ठहराव के बारे में हम सोच नहीं पाते। लगातार जुटे रहते हुए हमारा ध्यान इस बात पर जाता नहीं कि वास्तव में इतने क्रियाशील और अधिक व्यस्त हो गए हैं कि रुकने, थमने का थोड़ा भी समय हम नहीं निकाल पा रहे।

हम सभी के पास सीमित शारीरिक क्षमता होती है। अपने सामर्थ्य से अधिक काम करने पर थक जाना एक स्वाभाविक लक्षण है। हमें विश्राम की जरूरत पड़ने लगती है। विचारों के उद्वेग से उत्पन्न मानसिक दबाव को लंबे समय तक झेला तो जा सकता है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव हमारे मस्तिष्क को भी थकाने का काम करता है। यही कारण है कि मनुष्य को नींद लेने

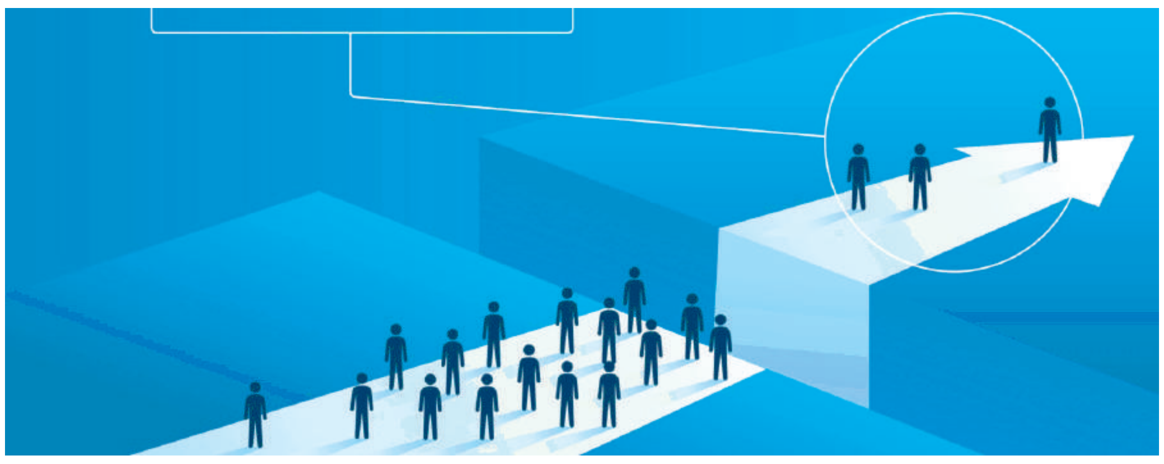

की नैसर्गिक सौगात मिली हुई है। यह एक ऐसा दैनिक ठहराव या विश्राम का दैनिक पड़ाव है, जिससे हमारे तन और मन का जरूरी रखरखाव होता रहता है।

जल्दी से जल्दी गंतव्य तक पहुंचने की जिद में शरीर और दिमाग को तेज दौड़ाने के प्रयास भी हम करते हैं कभी-कभी। दिमाग को निरंतर अनावश्यक रूप से सक्रिय बनाए रखते हैं। थोड़ी फुर्सत में खाली बैठते हैं, तब भी दिमाग मे कोई न कोई विचार उछलकूद करता रहता है। भूतकाल के कष्ट और भविष्य के सपने और सवाल मन को बेचैन बनाए रहते हैं। जबकि वर्तमान, जो हमारा वास्तविक जीवन है, उसमें सक्रियता और ठहराव के लिए निकट के प्रत्यक्ष अवसर हम नहीं देख पाते। मानसिक विश्राम को लेकर समाज में, हमारे खुद के मन में बड़ी उदासीनता मौजूद है। रात को भरपूर नींद लेना या किसी पर्यटन स्थल पर चले जाना ही जीवन में ठहराव नहीं है। इस जरूरी सुकून और ठहराव के लिए रोजमर्रा की गतिविधियों में भी अपने ध्यान को केंद्रित कर राहत और विश्राम के पलों को जीया जा सकता है। किसी निर्माणाधीन मकान के सामने आराम से बैठ कर उसके बनने की प्रक्रिया को निहारने के अलावा किसी बगीचे में माली को काम करते या बालकनी में बैठकर सड़क की ओर देखा जा सकता है। समय निकालकर अपनी घरेलू सहायक या सहायिका के दुख-दर्द को सुना और उसकी खुशियों के भागीदार बना जा सकता है। जिन्हें हम देख रहे हैं, वे क्रियाशील और हम विश्राम की स्थिति में होते हुए भी थकान का अनुभव करने लगते हैं।

कई बार गैरजरूरी सक्रियता के चंगुल में हम फंस जाते हैं। जब शरीर को आराम देने का वक्त होता है, तब भी हम लगातार सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पढ़, देख रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी किसी एक गतिविधि को लंबे समय तक प्रसारित करते हुए सक्रिय बने रहते हैं। यह सक्रियता अनावश्यक -सी व्यस्तता में तब्दील हो जाती है। यह हमें ऊर्जा तो नहीं देती, थकावट अवश्य दे जाती है। सक्रियता के साथ ठहराव को भी खुले मन से स्वीकार करने की जरूरत है। हमने ठहरना ठीक से सीखा नहीं है। हम अपने आप को सक्रियता, दौड़-भाग से अलग करके सोच ही नहीं पाते। जब हम खुद को बंधे - बंधाए प्रारूप मुक्त करके तनिक ठहराव की मानसिकता बनाएंगे तो सचमुच एक खूबसूरत दुनिया हमारे सामने होगी।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कोर चंद वाली मंडी हरजी राम वाली मलोट पंजाब

रिन्यूएबल एनर्जी में भारत ने गाड़े झंडे, लेकिन चीन पर कब खत्म होगी निर्भरता?

परिवहन विशेष न्यूज

चीन रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भारतीय कंपनियों के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती है। जाहिर है कि चीनी आयात पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार के शुल्कीय व गैर-शुल्कीय कदम अभी भी बेअसर है। ऐसे में उद्योग जगत के विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अपनी मौजूदा नीति में बदलाव करने की जरूरत है खास तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लागू पीएलआई स्कीम में।

ई दिल्ली। एक दशक पहले सौर प्लांट के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माण में भारत कहीं नहीं था। देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की स्थापित क्षमता सिर्फ तीन हजार मेगावाट सालाना थी। आज यह क्षमता बढ़ कर 67 हजार मेगावाट हो चुकी है। अगले वित्त वर्ष 2025-26 तक यह क्षमता एक लाख मेगावाट हो जाएगी।

यह निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि दिखती है लेकिन देश की जरूरत को देखते हुए नाकाफी है। भारत में सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने के लिए जो भी प्लांट लगाये जा रहे हैं उनमें से अधिकांश में (80 फीसद से ज्यादा) चीन निर्मित मशीन व प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत अपनी जरूरत का 60 फीसद सोलर पीवी मॉड्यूल अभी भी चीन से आयात कर रहा है।

चीन इस सेक्टर में भारतीय कंपनियों के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती है। जाहिर है कि चीनी आयात पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार के शुल्कीय व गैर-शुल्कीय कदम अभी भी बेअसर है। ऐसे में उद्योग जगत के विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अपनी मौजूदा नीति में बदलाव करने की जरूरत है, खास तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लागू पीएलआई स्कीम में।

क्या चीन पर घट रही है हमारी निर्भरता

एक दिन पहले नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि देश में उच्च क्षमता के सोलर पीवी माड्यूल्स के निर्माण के लिए घोषित पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव- उत्पादन से जुड़ा हुआ प्रोत्साहन) नीति के तहत 24 हजार करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया है। इससे 47 हजार मेगावाट क्षमता के पीवी मॉडयूल्स के निर्माण के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है।

एमएनआरई मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हाल ही में संसद में बताया था कि सौर ऊर्जा संयंत्र में लगाने वाले सोलर पीवी सेल्स और पीवी मॉड्यूल की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता तेजी से कम हो रही है। उक्त दोनों उत्पादों पर चीन पर निर्भरता वर्ष 2022-23 में क्रमशः 94 व 93 फीसद थी जो वर्ष 2023-24 में घट कर 56 व 66 फीसद हो गई है।

चीन के साथ बढ़ते कारोबारी घाटे के पीछे एक कारण सौर ऊर्जा में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का बढ़ता आयात भी है। भारत ने वर्ष 2030 तक देश में तीन लाख मेगावाट सौर उर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इतनी बड़ी क्षमता के लिए उपकरण आपूर्ति करने में घरेलू उद्योग की कोशिशें नाकाफी है, लिहाजा चीन से ही इनका आयात जारी रखना बाध्यता होगी।

भारत के सोलर इंडस्ट्री की चुनौतियां

भारत की प्रमुख सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी सात्विक सोलर के सीईओ प्रशांत माथुर का कहना है कि सबसे पहले हमें अपनी पीएलआई स्कीम में बदलाव करने की जरूरत है। भारत सरकार की स्कीम समग्र सोलर सेक्टर के लिए है लेकिन दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जो सौर ऊर्जा से संबंधित सारे सेक्टरों के निर्माण में आत्मनिर्भर हैं।

उदाहरण के तौर पर पॉलीमर्स या वेफर्स के निर्माण की इकाई स्थापित करने में काफी निवेश होता है। पूरा वैल्यू चेन स्थापित करने के लिए काफी ज्यादा निवेश चाहिए। पालीमर्स या वेफर्स का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर उद्योग में भी होता है। यानी इनके निर्माण से जुड़ी कंपनियां सौर ऊर्जा के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग को भी आपूर्ति कर सकेंगी। लेकिन अगर अलग-अलग सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाए तो उसका ज्यादा फायदा दिख सकता है।

माथुर की दूसरा सलाह यह है कि भारत में जमीन अधिग्रहण की समस्या को दूर किया जाए। वह बताते हैं कि सौर ऊर्जा से जुड़े उद्योगों के लिए जमीन का अधिग्रहण एक बड़ी अड़चन है। इसे सरकार के स्तर पर ही दूर किया जा सकता है। कम ब्याज पर फंड और कुशल श्रम की कमी को भी वह अन्य अड़चन के तौर पर चिन्हित करते हैं। इन्हें दूर करके ही भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा।

पाकिस्तान के लिए IMF ने खोला खजाना; तारीफ में पढ़े कसीदे, लेकिन चेतावनी भी दी

पाकिस्तान फिलहाल गले तक कर्ज में डूबा है। उसकी आर्थिक स्थिति बदहाल है। वह बेलआउट पैकेज के लिए लगातार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से मिन्नतें कर रहा था। IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर का नया कर्ज मंजूर कर दिया है। यह कर्ज पाकिस्तान को 37 महीनों में किस्तों में मिलेगा। इसका मकसद पाकिस्तान की जर्जर अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में मदद करना है।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान के लिए सात अरब डॉलर के नए बेलआउट पैकेज को स्वीकृति दे दी है। नकदी संकट से जूझ रहे देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए 1.1 अरब डॉलर से कम की पहली ऋण किस्त को तत्काल जारी करने की अनुमति मिल गई है।

आईएमएफ बोर्ड की बुधवार को वॉशिंगटन में हुई बैठक में पाकिस्तान के साथ कर्मचारी स्तरीय समझौते को मंजूरी दी गई। इससे पहले पाकिस्तान ने अपने कृषि आयकर में सुधार करने, कुछ वित्तीय जिम्मेदारियों को प्रांतों को हस्तांतरित करने और सब्सिडी को सीमित करने का वादा किया था।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुष्टि की कि आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने 37 महीने की विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल राशि सात अरब डॉलर है। यह 1958 के बाद से पाकिस्तान को मिला 25वां आईएमएफ कार्यक्रम और छठा ईएफएफ है।

IMF ने की पाकिस्तान की तारीफ

IMF ने गुरुवार को जारी एक बयान में पाकिस्तान की तारीफ भी की है कि उसने आर्थिक बेहतरी के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जिसने विकास में तेजी आई है। साथ ही, महंगाई से जनता को राहत मिली है और वह सिंगल डिजिट में आ गई है। विदेशी मुद्रा बाजार में शांति है, इससे पाकिस्तान को रिजर्व भंडार को दोबारा भरने में मदद मिली।

हालांकि, IMF ने कुछ पहलुओं पर चिंता भी जताई। उसने चेतावनी दी कि पाकिस्तान भले ही तरक्की की राह पर बढ़ने लगा है, लेकिन उसकी कुछ संरचनात्मक चुनौतियां बनी हुई हैं। जैसे कि कारोबारी माहौल का मुश्किल है। कमजोर सरकार की वजह से निवेश में बाधा आ रही है।

IMF ने कहा कि सरकारी अधिकारी भी अड़ंगा लगाकर काम खराब रहे हैं। वहीं टैक्स बेस भी काफी छोटा बना हुआ है। साथ ही, सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी पर्याप्त खर्च नहीं कर रही।

अनिल अंबानी की पावर कंपनी में तेजी का करंट, लगातार छठें दिन लगा अपर सर्किट

अनिल अंबानी की कंपनी Reliance Power के शेयर ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल लगातार छठे दिन कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लगा है। इसका मतलब है कि निवेशक शेयर खरीदना चाह रहे हैं पर शेयरधारक स्टॉक बेचना नहीं चाह रहे हैं। आइए इस आर्टिकल में शेयर की परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की कंपनी के शेयर चर्चा में बना हुआ है। दरअसल, लगातार छठे दिन रिलायंस पावर के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। बता दें कि जब कई निवेशक कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं पर कोई शेयरधारक शेयर बेचना नहीं चाहता है तब अपर सर्किट लगता है।

26 सितंबर 2024 (गुरुवार) को भी कंपनी के शेयर 5 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 44.15 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया।

शेयर में क्यों जारी है तेजी

इस महीने 23 सितंबर 2024 को रिलायंस पावर की बोर्ड मीटिंग थी। इस मीटिंग में फंड जुटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। कंपनी घरेलू बाजार के साथ ग्लोबल मार्केट से भी फंड जुटाने की योजना बना रही है। बता दें कि हाल ही में अनिल अंबानी की दो कंपनियां का कर्ज कम हो गया। कर्ज कम होने के बाद कंपनी के शेयरों में तेजी आई है। रिलायंस पावर के साथ रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयर में भी तेजी देखने को मिली है।

रिलायंस पावर के शेयर परफॉर्मेंस

रिलायंस पावर के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के शेयर ने बीते एक साल में 132.37 फीसदी का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं इस साल मार्च से लेकर अभी तक कंपनी के शेयर में 59.96 फीसदी की तेजी आई है। कंपनी ने पिछले 5 सत्र यानी 20 सितंबर 2024 से आज तक में 21.49 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर का प्रदर्शन अच्छा रहा है।

ईशा-आकाश अंबानी के साथ शामिल है इन आंत्रप्रेन्योर का नाम, चेक करें पूरी लिस्ट

परिवहन विशेष न्यूज

हुरुन इंडिया ने Hurun India Under 35 List जारी की है। इस लिस्ट में 35 साल तक के Entrepreneur के नाम शामिल है। बता दें कि कम उम्र की महिला में ईशा अंबानी और परिता पारेख को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में किन Entrepreneur का नाम शामिल है।

नई दिल्ली। हुरुन इंडिया (Hurun India) ने साल 2024 के लिए हुरुन इंडिया अंडर 35 की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में वह सभी अरबपति युवा शामिल हैं जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। इस लिस्ट में पहली बार कम उम्र की महिला के रूप में ईशा अंबानी और परिता पारेख को शामिल किया गया है। इनके अलावा लिस्ट में मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के बेटे आकाश अंबानी और शेयरचैट के अंकुश सचदेवा का नाम भी शामिल हैं।

Hurun India Under 35 List में इतने हैं Entrepreneur

हुरुन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस लिस्ट में 82 फीसदी सेल्फमेड Entrepreneur हैं यानी जिन्होंने खुद से संपत्ति अर्जित की है। लिस्ट के अनुसार बैंगलुरु के 29 और मुंबई के 26 लोग शामिल हैं। अगर सेक्टर के हिसाब से देखें तो फाइनेंस सेक्टर के 21 लोगों का नाम शामिल है। इसके बाद सॉफ्टवेयर सेक्टर 14 आंत्रप्रेन्योर शामिल हैं। इस लिस्ट के जारी होने के बाद एक बात साफ हो गई है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम में सर्विस सेक्टर का बड़ा अहम रोल है। लिस्ट में सर्विस सेक्टर से जुड़े 59 फीसदी Entrepreneur है।

हुरुन लिस्ट में देश के 35 साल की उम्र तक के 150 Entrepreneur को शामिल किया गया है। बता दें कि हुरुन इंडिया इस लिस्ट में वह Entrepreneur शामिल हैं जिनके बिजनेस की वैल्यूएशन 50 मिलियन डॉलर है। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस Entrepreneur की वैल्यूएशन 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा है तो उन्हें भी इस लिस्ट में स्थान दिया गया है।

Hurun India Under 35 List में 7 महिलाओं का है नाम

Hurun India Under 35 List की लिस्ट में 7 महिलाओं का नाम है। इस लिस्ट में अनेरी पटेल, अनीशा तिवारी और अंजलि मर्चेंट जैसे Entrepreneur का नाम शामिल हैं। इन सब की आयु 35 वर्ष से कम है। ये सभी Entrepreneur अपुने फैमिली का बिजनेस जारी रखती है और वुमन लीडर्स लिस्ट में टॉप पर हैं।

बता दें कि इस लिस्ट में Traya Health की फाउंडर सलोनी आनंद और Mamaearth की फाउंडर गजल अलघ का नाम भी है।

आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत! 100 से अधिक वस्तुओं पर GST घटाने की तैयारी

परिवहन विशेष न्यूज

जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने आम जनता को राहत देने के लिए कई वस्तुओं पर टैक्स रेट कम करने पर विचार किया। इनमें साइकिल से लेकर बोतलबंद पानी तक कई चीजें हैं। सभी मंत्री इस बात पर एकमत दिखे कि जनता को राहत मिले। वहीं बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कम करने पर निर्णय लेने के लिए गठित मंत्रिसमूह की बैठक 19 अक्टूबर को होगी।

नई दिल्ली। 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को घटाया जा सकता है। बुधवार को जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर विचार किया। बैठक में आम आदमी को राहत देने के लिए साइकिल और बोतलबंद पानी सहित कुछ अन्य वस्तुओं पर कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत पर भी चर्चा की गई। इस दौरान 12 प्रतिशत स्लैब में शामिल चिकित्सा और फार्मा से संबंधित वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी का मुद्दा भी उठा और इस पर आगे होने वाली बैठक में विस्तृत चर्चा करने पर सहमति भी बनी।

क्या सस्ता होगा, क्या महंगा?

अभी साइकिल और उसके पुर्जे और सहायक उपकरण पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि ई-साइकिल पर पांच प्रतिशत कर लगता है। बैठक में शामिल पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि कर की दर कम करने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सोडा वाटर और पेय पदार्थों सहित कुछ अन्य वस्तुओं पर कर की दरों को मौजूदा 28 प्रतिशत और उस पर लगने वाले उपकर को बढ़ाने की संभावना पर भी चर्चा की गई।

चंद्रिमा ने कहा कि आम आदमी द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर की दरों को कम किया जाना चाहिए और खाद्य पदार्थों से जुड़ी चीजों को 12 प्रतिशत से पांच प्रतिशत के स्तर पर लाया जाना चाहिए।

टैक्स स्लैब में कमी को लेकर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। जीओएम में आम सहमति थी कि आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए और इस बात पर भी सभी एकमत थे कि अगर आम आदमी से जुड़ी वस्तुओं पर कर की दरों को कम किया जाता है तो उससे होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए नए विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

चंद्रिमा भट्टाचार्य, वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल

GST काउंसिल करेगी आखिरी फैसला

20 अक्टूबर को होने वाली बैठक के बाद जीओएम अपनी सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखेगा, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं। वर्तमान में जीएसटी प्रणाली एक चार स्तरीय कर संरचना है, जिसमें पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की स्लैब हैं।

हालांकि, जीएसटी कानून के अनुसार, वस्तुओं और सेवाओं पर 40 प्रतिशत तक का कर लगाया जा सकता है। जीएसटी के तहत आवश्यक वस्तुओं को या तो कर से छूट दी गई है या उन पर सबसे कम कर लगाया गया है। जबकि विलासिता से जुड़ी वस्तुओं पर सबसे अधिक 28 प्रतिशत जीएसटी और उपकर लगता है।

इंश्योरेंस प्रीमियम पर घटेगी जीएसटी?

स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को कम करने पर निर्णय लेने के लिए गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) की पहली बैठक 19 अक्टूबर को होगी। मंत्रिसमूह को अक्टूबर के अंत तक जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। मंत्री समूह की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर में होने वाली अगली बैठक में बीमा प्रीमियम पर कराधान पर परिषद द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में अपनी बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह गठित करने का निर्णय लिया था। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। इस समिति में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं।

एक अधिकारी ने बताया, मंत्रिसमूह को वरिष्ठ नागरिकों, मध्यम वर्ग, मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए व्यक्तिगत, समूह, पारिवारिक फ्लोटर और अन्य चिकित्सा बीमा सहित स्वास्थ्य/चिकित्सा बीमा की कर दर का सुझाव देने को कहा गया है। दरअसल, सबसे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को हटाने की मांग की थी। इस पर उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भी लिखा था।

फेस्टिव सीजन में बढ़ाना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट? जानिए किन बातों पर गौर करते हैं बैंक

परिवहन विशेष न्यूज

आज के समय में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी अधिक हो गया है। इस प्लास्टिक मनी के जरिए शॉपिंग करने से लेकर बिल चुकाने तक में काफी सहूलियत होती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने में कई बार लिमिट की समस्या आती है। आइए जानते हैं कि बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट कब बढ़ाते हैं और वे किन बातों पर गौर करते हैं।

नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन में ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म से लेकर फिजिकल स्टोर तक हर तरफ खरीदारी का माहौल है। कई जगहों पर क्रेडिट कार्ड पर नो-कॉस्ट EMI के साथ शानदार डिस्काउंट का ऑफर मिल रहा है। लेकिन, ऐसे वक्त में कई बार हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो जाती है और हम अच्छे डिस्काउंट के साथ अपनी जरूरत का सामान खरीदने का मौका चूक जाते हैं।

आइए जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे बढ़वाई जा सकती है और बैंक लिमिट बढ़ाने से पहले किन बातों पर गौर करते हैं।

क्या होती है क्रेडिट कार्ड लिमिट?

बैंक या कोई अन्य वित्तीय संस्थान जब आपको क्रेडिट कार्ड जारी करता है, तो यह एक लिमिट के साथ आता है। इसका मतलब कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30 हजार रुपये है, तो आप एक साइकल में इससे अधिक नहीं खर्च कर सकते। क्रेडिट कार्ड की लिमिट अमूमन ग्राहक की आमदनी के हिसाब से तय होती है। यह कार्ड के हिसाब से भी अलग-अलग हो सकती है।

किन चीजों पर गौर करते हैं बैंक

बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट तय करने से पहले कई चीजों पर गौर करता है। जैसे कि आपकी सालाना कमाई कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, आपके ऊपर कितना कर्ज है और आप किस तरह का रोजगार करते हैं यानी आपका नौकरीपेशा हैं या कारोबारी। साथ ही, क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

बैंक कब बढ़ाते हैं क्रेडिट लिमिट

बैंक अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आप बकाया का भुगतान सही समय पर करते हैं, तो बैंक अपनेआप भी आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ा सकता है। आप खुद भी अपनी जरूरत के हिसाब से लिमिट बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इस सूरत में बैंक आपके खर्च और कमाई के अनुपात जैसी चीजों पर भी गौर करते हैं। सबकुछ रहने की सूरत में वे लिमिट बढ़ा देते हैं।

क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के तरीके

बैंक समय-समय पर खुद क्रेडिट लिमिट बढ़ा देते हैं, अगर ग्राहक का क्रेडिट स्कोर अच्छा है और वे बिल पेमेंट वक्त पर करते हैं।

आप अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता से सीधे संपर्क कर सकते हैं और अपनी लिमिट बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

कई बैंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने ग्राहक को क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए अनुरोध करने की सहूलियत देते हैं।

अगर आपका क्रेडिट स्कोर (CIBIL Score) अच्छा है, तो आपको अधिक क्रेडिट लिमिट मिलने की संभावना होती है।

दिल्लीवासी ध्यान दें! आवेदन के 24 घंटे के अंदर मिलेगा अस्थायी बिजली कनेक्शन; जानें कैसे करें अप्लाई

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्लीवासियों को तत्काल बिजली कनेक्शन लेने के लिए परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तत्काल कनेक्शन के लिए बीएसईएस राजधानी पावर लिमटेड (बीआरपीएल) उपभोक्ता को 19123 और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) उपभोक्ता 19122 पर फोन करके या बीएसईएस कस्टमर केयर सेंटर/ डिजी सेवा केंद्र पर जाकर सामान्य व्यावसायिक औपचारिकताओं को पूरा कर सकते हैं। बीएसईएस की वेबसाइट मोबाइल ऐप पर भी आवेदन किया जा सकता है।

नई दिल्ली। वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखकर बिजली वितरण कंपनियों ने आवेदन करने के 24 घंटे के अंदर बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। बीएसईएस ने इसके लिए तत्काल सेवा शुरू की है। इससे रामलीला, दुर्गा पूजा और अन्य आयोजन करने वाली संस्थाओं को होगा।

बीएसईएस अधिकारियों ने कहा, "प्रदूषण के रोकथाम के लिए डीजल से चलने वाले जनरेटर पर प्रतिबंध है। सामान्य तौर पर अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है। त्योहार के समय आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को ध्यान में तत्काल सेवा शुरू की गई है। शादी समारोहों व अन्य कार्यक्रमों के लिए भी तत्काल कनेक्शन दिए जाएंगे।"

जनरेटर की तुलना में सस्ती बिजली मिलेगी

उन्होंने कहा कि इससे नवरात्रि, रामलीला, दुर्गा पूजा और दीपावली के समय आयोजित होने वाले आयोजनों में बिजली से संबंधित परेशानी नहीं होगी। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और आयोजकों को डीजल से चलने वाली जनरेटर की तुलना में सस्ती बिजली मिलेगी। 24 घंटे के भीतर अस्थायी कनेक्शन पाने के लिए उपभोक्ताओं को आवेदन करते वक्त सभी जरूरी कागजात देने के साथ डिमांड नोट का भुगतान करना होगा।₹

तत्काल कनेक्शन के लिए ऐसे करें आवेदन

उन्होंने कहा कि तत्काल कनेक्शन के लिए बीएसईएस राजधानी पावर लिमटेड (बीआरपीएल) उपभोक्ता को 19123 और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) उपभोक्ता 19122 पर फोन करके या बीएसईएस कस्टमर केयर सेंटर/ डिजी सेवा केंद्र पर जाकर सामान्य व्यावसायिक औपचारिकताओं को पूरा कर सकते हैं। बीएसईएस की वेबसाइट, मोबाइल ऐप पर भी आवेदन किया जा सकता है।

संस्कारशाला: कैलीग्राफी - आज के युग में महत्व : आर्ट निर्भर भारत

कैलीग्राफी, यानि सुलेख, न केवल एक कला है बल्कि यह एक अद्भुत ध्यान प्रक्रिया भी है जो मन को शांति और संतोष प्रदान करती है। डिजिटल युग में, जब तकनीक ने हर क्षेत्र में अपनी जगह बना ली है, तब भी हाथ से लिखने का महत्व कम नहीं हुआ है। बल्कि, हाथ से लिखी गई चीजों का एक अलग ही भावनात्मक और सांस्कृतिक मूल्य होता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आर्ट निर्भर भारत अभियान के तहत डॉ. अंकुर शरण ने कैलीग्राफी को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है।

डॉ. शरण के अनुसार, कैलीग्राफी सिर्फ सुंदर अक्षर लिखने की कला नहीं है, बल्कि यह ध्यान का एक रूप है, जो व्यक्ति को संतुलित और केंद्रित रहने में मदद करती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर चीज तुरंत चाहिए, वहां कैलीग्राफी एक ठहराव की भावना लाती है। जब आप किसी को हाथ से लिखा हुआ स्मृति-चिह्न देते हैं, तो वह सिर्फ एक वस्तु नहीं होती, बल्कि उसमें समय, मेहनत और भावनाएं जुड़ी होती हैं, जो उसे और भी मूल्यवान बनाती हैं।

आर्ट निर्भर भारत अभियान के माध्यम से, डॉ. शरण न केवल कैलीग्राफी को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि उन विद्यार्थियों का भी समर्थन कर रहे हैं जो इस सुंदर कला को सीखने के इच्छुक हैं। यह अभियान उन छात्रों को प्रेरित करता है जो कैलीग्राफी को अपने शौक के रूप में अपनाना चाहते हैं और इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना चाहते हैं।

आज के डिजिटल युग में भी, हाथ से लिखने का महत्व बना हुआ है। लिखने की प्रक्रिया केवल सूचनाओं को संप्रेषित करने तक सीमित नहीं है, यह हमारी भावनाओं और व्यक्तित्व को भी व्यक्त करती है। कैलीग्राफी के माध्यम से हम न केवल सुंदर लेखन कर सकते हैं, बल्कि यह हमें धैर्य, संतुलन और आत्म-अनुशासन भी सिखाती है।

कैलीग्राफी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कला और साहित्य को एक साथ जोड़ सकते हैं। यह न केवल हमारे हाथों और मस्तिष्क के बीच के तालमेल को बढ़ाता है, बल्कि यह हमारी सृजनशीलता को भी नई दिशा देता है। आर्ट निर्भर भारत अभियान के माध्यम से, डॉ. अंकुर शरण इस कला को हर वर्ग तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस कला के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।

कैलीग्राफी का अभ्यास करने से न केवल हमारे लेखन कौशल में सुधार होता है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क को भी सक्रिय और सकारात्मक बनाए रखता है। आज, जब तकनीक ने हमारी दिनचर्या को तेज और त्वरित बना दिया है, ऐसे में कैलीग्राफी हमें धीमेपन और शांति का महत्व सिखाती है।

आर्ट निर्भर भारत

व्यक्तित्व की पहचान: सुंदर हस्तलिपि व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती है और उसकी संजीदगी और अनुशासन का प्रतीक होती है।

पाठन में सहूलियत: साफ-सुथरी और सुंदर लिखावट से पाठ को पढ़ना आसान हो जाता है, जिससे संप्रेषण अधिक स्पष्ट होता है।

ध्यान और एकाग्रता: सुंदर हस्तलिपि के लिए धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्ति की एकाग्रता और मानसिक संतुलन में सुधार होता है।

सृजनात्मकता का विकास: हस्तलिपि को कला के रूप में देखना सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, जिससे लेखन का सौंदर्य और भी निखरता है।

शिक्षा में लाभ: बच्चों में सुंदर लिखावट के विकास से उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होता है, क्योंकि यह उन्हें अनुशासित और केंद्रित बनाता है।

सकारात्मक प्रभाव: सुंदर हस्तलिपि से लिखी गई वस्तुएं, जैसे पत्र या नोट्स, पढ़ने वाले पर सकारात्मक और सुखद प्रभाव छोड़ती हैं।

संवेदनशीलता और भावनात्मक जुड़ाव: हाथ से लिखी गई चीज़ें, विशेषकर सुंदर लिखावट में, व्यक्तिगत और भावनात्मक महत्व रखती हैं, जो गहरे रिश्तों को मजबूत करती हैं।

स्मरण शक्ति में सुधार: हाथ से लिखने का अभ्यास मस्तिष्क को अधिक सक्रिय करता है और स्मरण शक्ति में सुधार लाता है, जिससे लिखी गई चीजें अधिक समय तक याद रहती हैं।

विरासत का संरक्षण: सुंदर लिखावट एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है।

आर्ट निर्भर भारत के माध्यम से, डॉ. अंकुर शरण ने हजारों विद्यार्थियों को कैलीग्राफी के साथ-साथ इसे उनके दैनिक जीवन में शामिल करने और इसे एक भावनात्मक जुड़ाव के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। जब आप किसी को अपनी कलम से कुछ लिखकर देते हैं, तो वह सिर्फ एक शब्द या वाक्य नहीं होता, बल्कि उसमें आपकी मेहनत, समय, और भावना जुड़ी होती है। यह एक खास तरह का भावनात्मक बंधन उत्पन्न करता है जो डिजिटल माध्यमों से संभव नहीं हो पाता।

डॉ. शरण ने विद्यार्थियों को सिखाया है कि जब वे किसी को अपने हाथ से लिखी हुई वस्तु भेंट करते हैं, तो वह एक अनमोल उपहार बन जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा वे न केवल अपनी लेखन कला को सुधारते हैं बल्कि दूसरों के साथ गहरा जुड़ाव भी महसूस करते हैं। आर्ट निर्भर भारत का यह अभियान विद्यार्थियों में कैलीग्राफी और हस्तलिपि की महत्ता को स्थापित करने के साथ-साथ, उन्हें इस कला के माध्यम से अपने विचार और भावनाओं को प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम प्रदान कर रहा है।

इसलिए, आर्ट निर्भर भारत अभियान के साथ जुड़ें और इस अनमोल कला को सीखें, समझें और आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे समाज में लेखन और कला का महत्व सदैव बना रहे।

LG का आदेश- मयेर तुरंत कराएं स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव, MCD आयुक्त से 10 बजे तक मांगी रिपोर्ट

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महापौर शैली ओबेरॉय को तुरंत स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव कराने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि महापौर की बैठक की अध्यक्षता करें। अगर महापौर चुनाव के लिए राजी नहीं होती है तो उप-महापौर अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद भी अगर नहीं होते हैं तो वरिष्ठ पार्षद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एलजी ने इसके साथ ही रात 10 बजे तक रिपोर्ट मांगी है।

नई दिल्ली। उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना ने महापौर शैली ओबेरॉय को आदेश दिए कि तुरंत स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव कराया जाए। उपराज्यपाल ने एक बार फिर एमसीडी एक्ट अनुच्छेद 487 का उपयोग करते हुए कहा कि महापौर की बैठक की अध्यक्षता करें। अगर महापौर चुनाव के लिए राजी नहीं होती हैं तो उप-महापौर अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद भी अगर, नहीं होते हैं तो वरिष्ठ पार्षद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एलजी ने इसके साथ ही रात 10 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर एमसीडी आयुक्त ने महापौर और उप-महापौर को स्थायी समिति के छठे सदस्य के लिए चुनाव कराने और उपराज्यपाल के निर्देशों का पालन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है।

10 बजे तक रिपोर्ट सौंपने को कहा : एलजी सक्सेना ने एमसीडी आयुक्त को स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव के संचालन की रिपोर्ट आज रात 10 बजे तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यदि महापौर अनुपस्थित हैं या बैठक की अध्यक्षता करने से इनकार करती हैं, तो उप-महापौर से चुनाव संचालन के लिए बैठक की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया जा सकता है। यदि दोनों अनिच्छुक या अनुपलब्ध हैं, तो वरिष्ठता के क्रम में सबसे वरिष्ठ सदस्य से यह कार्य करने का अनुरोध किया जा सकता है।

मनीष सिसोदिया करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस : वहीं इन सारी घटनाक्रमों पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने लिखा- भाजपा के LG साहब द्वारा गैर-कानूनी और गैर-संवैधानिक तरीके से MCD Standing Committee के चुनाव करवाने की कोशिश पर अब से कुछ देर में 9:30 बजे प्रेस कांफ्रेंस करूंगा।

कब क्या हुआ : दोपहर 12- सिविक सेंटर में भारी पुलिस बल तैनात, लोगों को जांच के बाद प्रवेश दिया जा रहा था।

1 बजे- दिल्ली कांग्रेस ने घोषणा की वह मतदान में हिस्सा नहीं लेगी।

2 बजे- सदन में पार्षद सदन में आने शुरू हुए।

2.03- पार्षद आने शुरू हुए पुलिस ने जांच के लिए रोका तो आप पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया।

2.10- बजे पर जांच कराकर भाजपा पार्षद सदन में पहुंच गए।

2.32- बजे महापौर निगम सदन में पहुंची और पहली बार बैठक को 15 मिनट के स्थगित किया और निगमायुक्त व निगम सचिव को निर्देश दिए कि वह पार्षदों को बिना तलाशी के सदन में आने दें।

2.35- बजे आयुक्त अश्विनी कुमार ने कहा कि सदन में मोबाइल के अलावा इलेक्ट्रानिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं है। इससे चुनाव की गोपनीयता भंग हो सकती है।

विश्व फार्मासिस्ट दिवस विशेष : हमारे स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फार्मासिस्ट : डॉ. रवींद्र सिंह राना

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा, संजय साग़र सिंह। 25 सितंबर को हर वर्ष दुनिया भर के लोग विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाते हैं। इस अवसर पर एस एन मेडिकल कॉलेज आगरा के रिसेप्शन हाल में स्वास्थ्य सेवा के गुमनाम नायकों, फार्मेसी और फार्मासिस्टों का सम्मान किया गया। जो जनता की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं।

इस अवसर पर फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संगठन मंत्री एवम जिलामंत्री डी पी ए आगरा डॉ रवींद्र सिंह राना ने सभी साथियों को विश्व फार्मासिस्ट दिवस की हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री राणा ने कहा, विश्व फार्मासिस्ट दिवस एक विशेष दिन है जो हमारे जीवन में फार्मासिस्टों और फार्मेसी पेशेवरों के अविश्वसनीय योगदान को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए समर्पित है। फार्मासिस्ट हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और हम उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, जो जनता के स्वास्थ्य और भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। फार्मासिस्ट आम जनता के स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो दवाओं के बारे में जनता के सवालों के जवाब देते हैं। इसी वजह से वे जनता के स्वास्थ्य के संरक्षक हैं। वे जनता के भरोसेमंद सलाहकार भी हैं, फार्मासिस्ट सच्चे स्वास्थ्य सेवा नायक हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएं। इसीलिए फार्मासिस्ट हमारे स्वास्थ्य के मूक स्तंभ हैं, और उनकी प्रतिबद्धता हमारी प्रशंसा की हकदार है।

उन्होंने कहा, आज की तेज़ रफ़्तार दुनिया में, जहाँ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ सर्वोपरि हैं, फार्मासिस्ट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को बेहतर बनाने में फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।लेकिन फार्मासिस्टों को अक्सर स्वास्थ्य सेवा के गुमनाम नायक कहलाते हैं। क्योंकि उनके स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इस योगदान को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट उचित दवाओं को रोगियों तक पंहुचाने के लिए एक कड़ी की तरह कार्य करते हैं। उनका काम सिर्फ़ दवाइयाँ बाँटने से कहीं बढ़कर है, वे ही हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को सही दवाइयाँ, सही खुराक और सही निर्देशों के साथ मिलें। फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, इसीलिए फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवा के मामले में सबसे आगे हैं, फार्मासिस्ट डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोगियों को सर्वोत्तम संभव देखभाल मिले।

उन्होंने आगे कहा, फार्मासिस्ट दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी विषयों के बारे में जनता को शिक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे किसी भी संभावित परस्पर क्रिया या साइड इफ़ेक्ट की पहचान करने के लिए मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड और नुस्खों की समीक्षा भी करते हैं। फार्मासिस्ट मरीजों पर उनकी दवाओं के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी करते हैं। यदि किसी मरीज को कोई प्रतिकूल प्रभाव महसूस होता है, तो फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ मिलकर दवा को समायोजित कर सकते है या कोई दूसरी दवा लिख सकते है। इसीलिए हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फार्मासिस्टो के योगदान को पहचानने और उन्हें सम्मान देने के लिए यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। फार्मासिस्ट ही हैं जो हमें दवा की दुनिया में नवीनतम विकास के बारे में सूचित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमें सबसे प्रभावी और सुरक्षित उपचार मिले। ये वे व्यक्ति हैं जो जनता के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सरिता आगलेचा ने सीआई एमए ऑपरेशनल केस स्टडी किया पुरा

परिवहन विशेष न्यूज

हैदराबाद: करमनघाट समाज की होनहार प्रतिभा सरिता आगलेचा सुपुत्री हंसाराम सीरवी पूर्व अध्यक्ष अलमासगुड़ा बढेर, करमनघाट। मूलनिवासी गांव कोलपुरा, धनला, पाली वर्तमान करमनघाट हैदराबाद सरिता आगलेचा ने चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स सीआई एमए में ऑपरेशनल केस स्टडी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अकाउंटेंट में कम्प्लीट की। सरिता आगलेचा ने सीआई एम ए ऑपरेशनल केस स्टडी में अपनी प्रबंधन और विश्वेषणात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर सरीता को सीरवी समाज करमनघाट के पदाधिकारियों एवं समाज बंधुओ ने बधाई दी। सरिता आगलेचा ने बताया कि कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 92 प्रतिशत व 12th बोर्ड 88 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, इसके पश्चात डिग्री बीबीए में 9 जीपीए रहा। सरिता के पिता हंसाराम आगलेचा ने बताया कि शरू से ही सरिता की पढाई में अच्छी रुचि रही।

संबलपुर हाईवे भाइगिरी पर एक युवक ने कार के ऊपर बैठकर झंडा लहराते हुए बनाया वीडियो

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर: संबलपुर राजमार्ग पर भाइगिरी। युवक ने सड़क पर कब्जा कर लिया और कार के ऊपर बैठकर झंडा लहराते हुए वीडियो बनाया। 2 लोग कार के बोनट पर बैठे हैं, 4 लोग कार के 4 दरवाजों पर बैठे हैं और एक शख्स वीडियो शूट कर रहा है। यह घटना खोड़ जिला कलेक्टर कार्यालय के पीछे हुई, जबकि एसपी कार्यालय और जिलामाजिस्ट्रेट कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई।साथ ही यह सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। एसपी ने बताया कि नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट ले जाए गया है। एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। एसपी मुकेश भामू ने बताया कि कार भी जब्त कर ली गई है। एसपी ने कहा कि जल्द ही अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023